



वो मर जाएगा, लेकिन झुकेगा नहीं..., पुष्पा स्टाइल में संजय राउत ने किया कुणाल कामरा का समर्थन

मुंबई। राउत ने कहा कि कलाकार कथित धमकियों से डरने या समर्पण करने की बजाय मरना पसंद करेंगे। उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता कि कुणाल कामरा को कौन धमका रहा है और क्यों। कुणाल कामरा को मैं कई सालों से जानता हूँ। वह ऐसे कलाकार नहीं हैं जो धमकियों से डर जाएं। वह झुकेगा नहीं। कुणाल कामरा को बुधवार को शिवसेना नेता संजय राउत का समर्थन मिला। राज्यसभा सांसद ने महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के खिलाफ कॉमिडियन के "गद्दार" वाले बयान को लेकर उठे विवाद के बीच अपना समर्थन व्यक्त किया। राउत ने कहा कि कलाकार कथित धमकियों से डरने या समर्पण करने की बजाय मरना पसंद करेंगे। उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता कि कुणाल कामरा को कौन धमका रहा है और क्यों। कुणाल कामरा को मैं कई सालों से जानता हूँ।

शेष पेज 2 पर

वीरता-राष्ट्रभक्ति पर कोई सवाल नहीं, राणा सांगा मामले में अखिलेश यादव ने लिया यू-टर्न



लखनऊ। विवाद बढ़ता देख अब सपा मुखिया की तरफ से भी इसपर बयान आ गया है। राणा सांगा मामले में अखिलेश यादव ने विवाद बढ़ने के बाद अब यू-टर्न ले लिया है। अखिलेश यादव ने कहा कि राणा सांगा की वीरता राष्ट्रभक्ति पर कोई सवाल नहीं है। अखिलेश ने कहा कि इतिहास पुरुष का अपमान करना उद्देश्य नहीं है।

मेवाड़ के सबसे बड़े महाराणा, एक ऐसे व्यक्ति जो शासक के तौर पर हिंदपथ

आगरा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने सरकार के आठ साल पूरे होने पर 635 करोड़ की 128 योजनाओं का तोहफा दिया। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि आगरा की पहचान मुगलों से नहीं छत्रपति शिवाजी से है।

आगरा के जीआईसी मैदान में आए प्रदेश के मुखिया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने 635 करोड़ की 128 योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया।

प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जीआईसी मैदान पर अपनी



सरकार के 8 साल पूरे होने के मौके पर प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। जीआईसी मैदान पर उन्होंने 635 करोड़ रुपये की 128 योजनाओं का शिलान्यास

शिवाजी, राधारानी, बांके बिहारी और ब्रजभूमि से है। सीएम ने कहा कि प्रदेश सरकार विरासत सजाने के साथ विकास भी कर रही है। काशी, अयोध्या, प्रयागराज, नैमिषारण्य बटेश्वर इसके उदाहरण हैं। सीएम ने कहा कि सरकार युवाओं को रोजगार दे रही है। 8.50 लाख युवाओं को रोजगार मिला है। हाल में ही पुलिस भर्ती में 60 हजार युवाओं को नौकरी दी गई है। इनमें 12 हजार बेटीयां हैं।

सीएम ने कहा कि पहले की सरकार में गुंडे माफिया और दंगाई हावी थे।

लोकार्पण किया।

उन्होंने यहां मौजूद लाभार्थियों और लोगों से कहा आगरा की पहचान मुगलों से नहीं है, आगरा की पहचान छत्रपति

शेष पेज 2 पर

आईजी, डीजी, एआईजी एवं चार आईपीएस समेत एडिशनल एसपी के ठिकानों पर सीबीआई की दबिश

नेशनल प्रेस टाइम ब्यूरो

नई दिल्ली। सीबीआई की छापेमारी ने बुधवार को पूरे देश में हड़कंप मचा दिया है। देश में पहली बार हुआ है, जो चार आईपीएस क्वटर और दो एडिशनल एसपी सहित पूर्व मुख्यमंत्री और राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारी के ठिकानों पर एक साथ छापेमारी हुई है। सीबीआई ने अपने बयान में बताया है कि चार राज्यों के 60 से ज्यादा ठिकानों पर कार्रवाई चल रही है। दरअसल पूरा मामला छत्तीसगढ़ में महादेव सट्टा एप घोटाले से जुड़ा है। जांच में केन्द्रीय जांच ब्यूरो (उड़क) ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कई ठिकानों पर छापेमारी की। इस कार्रवाई की आंच प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, कांग्रेस विधायक देवेन्द्र यादव, पूर्व आईएएस अधिकारी अनिल टुटेजा सहित चार आईपीएस अधिकारियों तक पहुंच गई है।



उड़क ने रायपुर, भोपाल, कोलकाता और दिल्ली समेत 60 से अधिक स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया। उड़क की इस कार्रवाई में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ-साथ कई वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों और नौकरशाहों के ठिकानों पर छापे मारे गये। जिन अधिकारियों के खिलाफ जांच चल रही है, उनमें शामिल हैं: डॉ. आनंद खबड़ा

उस समय रायपुर और इंटेलिजेंस आईजी, वर्तमान में आईजी ट्रेनिंग। आरिफ शेख - उस समय रायपुर के एसएसपी, वर्तमान में आईजी सीएफ। प्रशांत अग्रवाल - उस समय रायपुर एसपी, वर्तमान में डीआईजी। डॉ. अभिषेक पल्लव- उस समय दुर्ग एसपी, वर्तमान में एआईजी। संजय धुव- उस समय एडिशनल एसपी दुर्ग। अभिषेक माहेश्वरी

- उस समय एडिशनल एसपी रायपुर और क्राइम एसपी। उड़क की टीम ने रायपुर स्थित अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (अरड) अभिषेक माहेश्वरी के घर भी छापा मारा, लेकिन घर पर कोई मौजूद न होने के कारण उसे सील कर दिया गया। महादेव सट्टा एप 2016 में छत्तीसगढ़ के तीन युवकों- सौरभ चंद्राकर, अतुल अग्रवाल और रवि उप्पल- द्वारा लॉन्च किया गया था। इस ऑनलाइन सट्टा प्लेटफॉर्म पर क्रिकेट, फुटबॉल, बैडमिंटन, टेनिस और अन्य खेलों के अलावा चुनाव परिणामों पर भी दांव लगाए जाते थे। धीरे-धीरे यह एप अवैध जुआ गतिविधियों का केंद्र बन गया। इसके प्रमोटर फिलहाल दुबई में हैं और जांच एजेंसियों को उन पर लोक सेवकों को हथसुरा धनदंड के रूप में मोटी रकम देने का संदेह है।

शेष पेज 2 पर

लोकसभा में क्या हुआ? स्पीकर की नसीहत पर क्यों नाराज हुए राहुल गांधी?

नई दिल्ली। लोकसभा में त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय विधेयक पर चर्चा की। सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा कि त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी विधेयक के पारित होने से ग्रामीण अर्थव्यवस्था का विकास होगा, रोजगार के नये अवसर पैदा होंगे। उन्होंने कहा कि मोदी जी के नेतृत्व में भारत को सहकारी क्षेत्र का पहला विश्वविद्यालय मिलेगा।

संसद की कार्यवाही के दौरान, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने दावा किया है कि उन्हें सदन में बोलने की अनुमति नहीं दी गई। उनकी टिप्पणी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा उन्हें प्रक्रिया के नियमों का पालन करने के लिए कहने के बाद आई है, जिसका पालन सदस्यों से सदन की गरिमा बनाए रखने के लिए अपेक्षित है। इस घटनाक्रम के बाद, कांग्रेस सांसदों ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात की और गांधी को सदन में बोलने का



अवसर न दिए जाने का मुद्दा उठाया, जिसे कांग्रेस नेता के बोलने के लिए खड़े होने पर स्थगित कर दिया गया। आज दोनों सदनों में सामान्य कामकाज भी हुआ। राज्य सभा में बैंकिंग कानून (संशोधन) विधेयक पर चर्चा हुई। लोकसभा में त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय विधेयक पर चर्चा की। सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा कि त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी विधेयक के पारित होने से ग्रामीण अर्थव्यवस्था का विकास होगा, रोजगार के नये अवसर पैदा होंगे। उन्होंने कहा कि मोदी जी के नेतृत्व में भारत को सहकारी क्षेत्र का पहला विश्वविद्यालय मिलेगा।

शेष पेज 2 पर

'ईद की सेवइयां खिलाना चाहते हैं तो गुझिया भी खानी पड़ेगी'

पीस कमेटी की बैठक में बोले सीओ अनुज चौधरी

संभल। पीस कमेटी की बैठक के दौरान हुई बातचीत में सीओ अनुज चौधरी का एक और बयान वायरल हो रहा है। वह वीडियो में शांति बनाए रखने की अपील करते हुए कहते हैं कि अगर आप ईद की सेवइयां खिलाना चाहते हैं तो आपको गुझिया भी खानी पड़ेगी।

संभल के सीओ अनुज चौधरी ने पीस कमेटी की बैठक में कहा कि पुलिस का उद्देश्य केवल कानून व्यवस्था बनाए रखना है, न कि किसी विशेष समुदाय के खिलाफ कार्रवाई करना। हम केवल इतना चाहते हैं कि शांति व्यवस्था बनी रहे और



कोई भी उपद्रव न हो। सीओ ने कहा कि अगर आप ईद की सेवइयां खिलाना चाहते हैं तो आपको गुझिया भी खानी पड़ेगी।

इससे पहले बैठक में एसपी श्रीशंभू ने स्पष्ट किया कि कोतवाली संभल क्षेत्र में मस्जिद और ईदगाह के अंदर ही नमाज अदा की जाएगी।

सड़कों पर किसी भी हालत में इसकी अनुमति नहीं दी जाएगी। नियमों के उल्लंघन की स्थिति में कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

प्रशासन ने सभी से शांति व्यवस्था बनाए रखने और नियमों का पालन करने की अपील की है।

शेष पेज 2 पर

'माओवाद'

लाल आतंक पर नकेल, वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित

जिलों की संख्या घटकर हुई '38', कब खत्म होगा 'माओवाद'?

नई दिल्ली। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 31 मार्च 2026 तक देश में वामपंथी उग्रवाद को पूरी तरह से समाप्त करने की घोषणा की है। इसके प्रमाण भी दिखने लगे हैं। अप्रैल 2018 तक वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित जिलों की संख्या 126 से घटकर 90 रह गई है, जुलाई 2021 तक यह संख्या 70 और फिर अप्रैल 2024 तक 38 रह गई है।

वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) के खतरे से समग्र रूप से निपटने के लिए, भारत सरकार (जीओआई) ने 2015 में 'एलडब्ल्यूई से निपटने के लिए राष्ट्रीय नीति और कार्य योजना' को मंजूरी दी थी। इस नीति में सुरक्षा संबंधी उपायों, विकास हस्तक्षेपों, स्थानीय समुदायों के अधिकारों और हकों को सुनिश्चित करने आदि से जुड़ी एक बहुआयामी रणनीति की



परिकल्पना की गई है। नीति के दृढ़ कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप हिंसा और भौगोलिक विस्तार में लगातार कमी आई है। वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित जिलों की संख्या में भी भारी गिरावट आई है। अप्रैल 2018 तक वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित जिलों की संख्या 126 से घटकर 90 रह गई है, जुलाई 2021 तक यह संख्या

70 और फिर अप्रैल 2024 तक 38 रह गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 31 मार्च 2026 तक देश में वामपंथी उग्रवाद को पूरी तरह से समाप्त करने की घोषणा की है।

केंद्रीय गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने बुधवार को राज्यसभा में पूछे गए एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह बात कही है। उन्होंने बताया,

वामपंथी उग्रवादियों (एलडब्ल्यूई) द्वारा हिंसा की घटनाएं जो 2010 में अपने उच्चतम स्तर 1936 पर पहुंच गई थीं, 2024 में घटकर 374 रह गई हैं। यानी 81 प्रतिशत की कमी आई है। इस अवधि के दौरान कुल मौतों (नागरिक + सुरक्षा बल) की संख्या भी 85 प्रतिशत घटकर 2010 में 1005 से 2024 में 150 हो गई है।

पिछले 06 वर्षों के दौरान, वामपंथी उग्रवादियों द्वारा हिंसा की घटनाएं जो 2019 में 501 थीं, 2024 में घटकर 374 हो गई हैं, यानी 25 प्रतिशत की कमी। इस अवधि के दौरान कुल मौतों (नागरिक + सुरक्षा बल) की संख्या भी 26 प्रतिशत घटकर 2019 में 202 से 2024 में 150 हो गई है।

शेष पेज 2 पर

ओआरसी सैनिक अकादमी ढीकोली के 5 छात्र आरआईएमसी देहरादून परीक्षा के लिए चयनित

नेशनल प्रेस टाइम ब्यूरो

बागपत। ढकोली स्थित ओआरसी सैनिक अकादमी ने अपने टीआरएफ बैच के 5 होनहार छात्रों की शानदार उपलब्धि की घोषणा की है, जिन्होंने प्रतिष्ठित राष्ट्रीय भारतीय सैन्य कॉलेज देहरादून की परीक्षा में सफलता प्राप्त की है।

यह उपलब्धि न केवल छात्रों की मेहनत और लगन को दर्शाती है, बल्कि अकादमी द्वारा दिए जाने वाले उत्कृष्ट मार्गदर्शन और प्रशिक्षण की गुणवत्ता को भी साबित करती है। चयनित छात्रों में चेतन्य झा और प्रणय झा, दोनों चंडीगढ़ से हैं, अरमान शर्मा



हरियाणा के चरखी दादरी से, कर्णिक नांदल पानीपत से और जितेश सिंह पंजाब के जीरकपुर से हैं। इन छात्रों के चयन से ओआरसी सैनिक अकादमी को गर्व महसूस हो रहा है, क्योंकि आरआईएमसी देहरादून भारत के सबसे प्रतिष्ठित सैन्य शिक्षण

संस्थानों में से एक है, जहां से प्रशिक्षित छात्र आगे चलकर भारतीय सशस्त्र बलों में अधिकारी के रूप में कार्य करते हैं। अकादमी ने हमेशा से ही अपने छात्रों को सिर्फ शिक्षाविदों तक सीमित न रखकर उन्हें शारीरिक फिटनेस, अनुशासन और नेतृत्व

कौशल में भी प्रशिक्षित किया है, जिससे वे कठिनतम परीक्षाओं में भी सफलता प्राप्त कर सकें। यह उपलब्धि इस बात का प्रमाण है कि संस्थान न केवल छात्रों के शैक्षणिक विकास पर ध्यान देता है, बल्कि उन्हें आत्मनिर्भर और जिम्मेदार नागरिक बनने के लिए भी प्रेरित करता है। अकादमी के निदेशक रंजीत रंजन झा ने इस मौके पर छात्रों और उनके अभिभावकों को बधाई देते हुए कहा कि यह सफलता केवल एक परीक्षा पास करने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह छात्रों के उज्ज्वल भविष्य की ओर बढ़ाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है।

ईट निमार्ता समिति मालिकों की समस्याओं पर की गयी चर्चा



बागपत। ईट निमार्ता समिति जनपद बागपत की ओर से मेरठ रोड स्थित वात्सायन पैलेस में हुए सेमिनार में राज्य कर विभाग, बागपत एवं बडौत के अधिकारियों के साथ परिचर्चा की गयी।

इस सेमिनार में राज्य कर विभाग के जौनल कमिश्नर, स्टेट जीएसटी हरीराम चौरसिया तथा ज्वाइन्ट कमिश्नर स्टेट जीएसटी अनीता गर्बाल द्वारा ईट निमार्ता समिति की विभिन्न समस्याओं को सुना गया तथा ईट निमार्ता इकाईयों से बिक्री पर बनने वाले समस्त कर को समय से जमा करने हेतु आग्रह किया गया। जिन फर्मों द्वारा समय से समस्त कर सही

रूप से जमा नहीं किया जा रहा है उनकी विअनुशा इकाई से जांच कराये जाने का निर्देश दिया गया। ईट निमार्ता समिति के अध्यक्ष विक्रम राणा, राजेन्द्र सिंह एवं महामंत्री नीरज नैन द्वारा ईट निमार्ता इकाईयों के समक्ष आने वाली विभिन्न समस्याओं पर चर्चा की गयी। उपायुक्त राज्य कर बागपत आरपी चौरसिया द्वारा बताया गया कि वैट अर्वाधि की तुलना में जीएसटी अर्वाधि में कुछ ईट निमार्ता इकाईयों द्वारा कम राजस्व जमा किया जा रहा है प्रतिवर्ष इसे बढ़ाने का आग्रह किया गया। जौनल कमिश्नर द्वारा विभाग द्वारा चलाई गई अर्धदण्ड एवं

ब्याज माफी योजना की भी जानकारी दी गयी। जिसके अन्तर्गत पारित वर्ष 2017-18, 2018-19 एवं 2019-20 के धारा-73 के अन्तर्गत पारित आदेशों में 31 मार्च 2025 तक कर जमा करने पर अर्धदण्ड एवं ब्याज माफ कर दिया जायेगा। सेमिनार में सहायक आयुक्त राज्य कर शशी प्रकाश, अशित मिश्र, आशीष माहेश्वरी तथा ईट निमार्ता समिति की ओर से विनोद गोयल, आनन्द पाल राणा, इन्द्रपाल सिंह, विक्रम कन्डेरा, मुकेश मित्तल, मुकेश शर्मा, नवीन गुप्ता, प्रमोद चैयरमैन, संजय प्रधान आदि उपस्थित रहें।

रजऊ हादसे के बाद टूटी पूर्ति विभाग की नींद, गैस गोदाम आबादी से हटाने के निर्देश

बरेली। रजऊ परसपुर में महालक्ष्मी गैस एजेंसी के गोदाम के पास सिलेंडरों से भरे ट्रक में हुए धमाकों के बाद पूर्ति विभाग के अधिकारी सक्रिय हो गए हैं। पूर्ति विभाग की तरफ से जिलेभर की ऑयल कंपनियों से जुड़ी गैस एजेंसियों और गोदाम संचालकों को नोटिस जारी किया गया है। सभी को मानक पूरे करने के साथ ही आबादी के बीच संचालित गोदामों को शहर से बाहर शिफ्ट करने के निर्देश दिए हैं। अभी भी शहर में कई स्थानों पर आबादी और बिजली की लाइन के पास गैस गोदाम संचालित हैं जिससे हर समय हादसे का खतरा बना रहता है। बिथरी चैनपुर थाना क्षेत्र के रजऊ परसपुर में सोमवार दोपहर सिलेंडर से भरे ट्रक में आग लगने से क्षेत्र में कई घंटे तक दहशत का माहौल रहा। इस विस्फोट के बाद इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिन्दुस्तान पेट्रोलियम के शहर में आबादी के बीच संचालित गैस गोदामों पर पूर्ति विभाग की नजर टेढ़ी हो गई है। हार्टमन पुल के पास स्थित गैस गोदाम, मिनी बाईपास के पास भी एक गैस गोदाम आबादी में है।

भजनलाल सरकार ने महिलाओं को बांटी सौगात श्रमिकों की बेटियों को अब भी केवल आस

खैरथल। राजस्थान दिवस समारोह के पहले दिन भजनलाल सरकार ने महिलाओं के खातों में कई योजनाओं का लाभ सीधे खाते में हस्तांतरित किया जिसका सभी वर्गों ने अपने हिसाब से हर्ष जताया

सीएम भजनलाल शर्मा राजस्थान के श्रम मंत्री भी हैं उनके विभाग में शिव शक्ति योजना के हजारों आवेदन वर्षों से पैडिंग पड़े हैं जिनका स्टेट्स पेंडिंग फीजीकल वैरीफिकेशन आज भी पोर्टल पर है,का पैसा राजस्थान दिवस पर महिला सम्मेलन भी नहीं मिलने पर श्रमिकों के परिवार और बेटियों में निराशा है श्रमिकों ने बातचीत में बताया सरकार को श्रमिकों की सूद भी लेनी चाहिए। मिली जानकारी के अनुसार सितंबर, 2018 में श्रम



विभाग की शुभ शक्ति योजना को बंद कर दिया गया। वर्ष 2021 में इसका पोर्टल भी बंद कर दिया गया।

इस समयावधि में जिले के सैकड़ों जरूरतमंद लोगों ने अपनी बेटी की शादी के लिए आर्थिक सहयोग पाने को लेकर आवेदन किए थे। असंगठित कामगार संघ से जुड़े जीतेंदर कुमार जांगिड़ ने बताया श्रमिकों

की बेटियों के लिए ये एक मात्र योजना थी जिससे श्रमिकों को बेटियों की उच्च शिक्षा और विवाह में सहायता मिलती थी ऐसी योजना को पैडिंग रखना और बंद करना किसी भी कल्याणकारी सरकार के लिए उचित नहीं सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए ऐसी योजना से बेटियों को सम्बल मिलता है

टटीरी का संस्कार शर्मा भारतीय सेना में बना लेफ्टिनेंट



नेशनल प्रेस टाइम ब्यूरो

बागपत। कस्बा अग्रवाल मंडी टटीरी के रामदास कालोनी निवासी संस्कार शर्मा सुपुत्र विपिन शर्मा का चयन भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट पद पर हुआ है।

कस्बा निवासी अरविंद शर्मा के भांजे संस्कार शर्मा का चयन लेफ्टिनेंट पद पर होने पर सभी लोगों ने उन्हें बधाई दी है। अरविंद शर्मा ने बताया की संस्कार शर्मा बागपत के क्रिस्तु ज्योति स्कूल का छात्र रहा है और उसने पढ़ते समय से ही सेना में जाकर देश की सेवा करने का लक्ष्य निर्धारित किया था, जो उसने कड़ी मेहनत से प्राप्त कर लिया है। संस्कार शर्मा प्रारम्भ से ही प्रतिभावान बच्चा रहा है और उसकी प्रारम्भिक शिक्षा बागपत के क्रिस्तु ज्योति स्कूल से हुई व स्नातक दिल्ली से हुई। उसके पिताजी दिल्ली में प्राइवेट नौकरी करते हैं व माता जी गृहणी है। उसकी इस कामयाबी पर नीरज एडवोकेट ,अनिरुद्ध शर्मा, धर्मपाल सिंह, सुभाष शर्मा, राधे कृष्ण शर्मा, विपिन शर्मा, मनोज भारद्वाज, डायरेक्टर ललिता शर्मा, सविता, अभिषेक व समस्त कालोनीवासियों ने उपस्थित होकर खुशिया मनाई।

डिस्काउंट पर बिक रही शराब, एक के साथ एक फ्री का बंपर ऑफर



शहर के श्यामतगंज, डीडीपुरम, पीलीभीत बाईपास, प्रेमनगर, राजेंद्र नगर में खुलेआम दुकानों पर बोर्ड और नोटिस लगाकर डिस्काउंट पर शराब बेची जा रही है। ऐसे में शराब के

शौकीनों की भी भीड़ लग गई है। लोग एक साथ कई महीने का स्टॉक तक कर ले रहे हैं। पूरी बॉक्स तक एक साथ लोग ले जाते हुए देखे गए।

बागपत के विपुल जैन हुए डीपीआईएफ 2025 इंटरनेशनल अवार्ड से सम्मानित

बागपत। नई दिल्ली में आयोजित डीपीआईएफ 2025 इंटरनेशनल अवार्ड समारोह में इंटरनेशनल अवार्ड व उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सम्मानित वरिष्ठ पत्रकार विपुल जैन बागपत को डीपीआईएफ 2025 इंटरनेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया।

विपुल जैन को दुबई के प्रमुख समाजसेवी, शीर्ष बिजनेसमेन एनएबीडी अल ऐमरेट के चैयरमैन व एनपीएम के सीईओ डाक्टर कबीर केवी द्वारा शॉल व पटका ओढ़ाकर व प्रतीक चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। डीपीआईएफ के संस्थापक कल्याणजी जाना ने कहा कि विपुल जैन को यह अवार्ड उनकी ईमानदारी, कर्तव्यनिष्ठा, धार्मिक व समाजसेवी कार्यों, साम्प्रदायिक सौहार्द में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने और राष्ट्रहित में किये जा रहे कार्यों के लिए प्रदान किया



गया है। बताया कि विपुल जैन एक बेहतरीन इंसान है और पूर्व में भी इंटरनेशनल और नेशनल स्तर की अनेकों संस्थाओं और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उनको सम्मानित किया जा चुका है। विपुल जैन निष्पक्ष पत्रकारिता के माध्यम से लोगों को इंसाफ दिलाने और समाज की छुपी हुई प्रतिभाओं को देश व दुनिया के सामने लाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। विपुल जैन ने अपनी इस उपलब्धि का श्रेय अपने दादा नरेन्द्र जैन, पिता सुदर्शन जैन, माता रेनु जैन, गुरुजनों सहित

उन सभी समस्त शुभचिंतकों व सहयोगियों को दिया, जिन्होंने उनको नेक कार्यों को करने के लिए जागरूक किया और जरूरतमंदों की सहायता करने के लिए तन-मन-धन से हर कदम पर उनका साथ दिया। विपुल जैन ने कहा कि मेरी इस उपलब्धि में वे सभी महान लोग बराबर के साझेदार हैं, जिनके सहयोग, आशीर्वाद और प्रार्थनाओं से वर्ष 2023-2024 में मुझे नवजीवन प्राप्त हुआ है। इस अवसर पर देश-विदेश से आयी जानी-मानी हस्तियां उपस्थित रही।

श्री दिगंबर जैन बड़ा मंदिर जी में हुआ भव्य शांति विधान का आयोजन



सुरेंद्र मलानिया

बड़ौत/बागपत- बड़ौत नगर के प्रतिष्ठित श्री दिगंबर जैन बड़ा मंदिर में शांति विधान का आयोजन बड़े धूमधाम और भक्तिपूर्ण माहौल में संपन्न हुआ। यह विशेष आयोजन पन्ना परिवार की संतोष जैन के (75वें) जन्मदिवस के शुभ अवसर पर किया गया।

इस धार्मिक विधान को छपरोली के ब्रह्मचारी भैया गौरव ने विधिपूर्वक संपन्न कराया। भैया गौरव जी के सान्निध्य में भक्तों ने मंत्रोच्चारण, भक्ति-भाव और श्रद्धा के साथ विधान में भाग लिया। करीब 100 श्रद्धालु इस पावन आयोजन में सम्मिलित हुए और भक्ति की भावधारा में डूबकर पुण्य लाभ अर्जित किया।

भक्ति और भजन संध्या से गूंज उठा मंदिर परिसर

शांति विधान के दौरान मंदिर में भजन-कीर्तन और नृत्य संगीत की मधुर स्वर लहरियों से भक्तिमय वातावरण बन गया। श्रद्धालुओं ने भक्ति गीतों के माध्यम से अपनी भावनाएं प्रकट कीं। मंदिर में गूंजते

जिनवाणी भजनों ने हर भक्त के हृदय को छू लिया।

आध्वर्जनक दिव्य

घटना बनी श्रद्धा का केंद्र विधान के समापन की ओर जब कार्यक्रम बढ़ रहा था, तभी वहां एक दिव्य घटना घटित हुई, जिसने श्रद्धालुओं को स्तब्ध कर दिया। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि विराजमान प्रतिमा जी पर केसर से स्वतः अभिषेक होने लगा और साथ ही प्रतिमा जी पर चंदन से स्वास्तिक बनता हुआ दिखाई दिया।

श्रद्धालुओं ने इस घटना को दैवीय चमत्कार मानते हुए इसे देवताओं की कृपा और आशीर्वाद की अनुभूति बताया। इस अलौकिक घटना को देखने वाले हर भक्त के मन में आस्था और भक्ति की लहर दौड़ गई।

मंदिर में श्रद्धालुओं की सहभागिता

इस पावन अवसर पर बड़ौत नगर के प्रवीण जैन, मंजू जैन, नवीन जैन, मोनिका जैन, कृतिका जैन, नीतीश जैन, अंकुर जैन, मयंक जैन, श्रुति जैन, मीनल जैन, सचिन जैन, नाम्या, संपदा, सार्थक, विदुषी, संकेत, डॉ. सुनीता जैन, कल्पना जैन, निशा, याशी, स्वस्ति, ऋषभ, तनीषा समेत कई गणमान्य श्रद्धालु उपस्थित रहे।

पन्ना परिवार ने इस भव्य आयोजन में भाग लेने वाले सभी श्रद्धालुओं का आभार व्यक्त किया और ईश्वर से सभी के सुख-समृद्धि और उत्तम स्वास्थ्य की कामना की। इस दिव्य और भक्तिमय आयोजन ने नगरवासियों के मन में आस्था और भक्ति की एक नई ऊर्जा का संचार किया।

बरेली कॉलेज रोजगार मेले के दौरान 337 का चयन

एनपीटी ब्यूरो

बरेली। बरेली कॉलेज में प्लेसमेंट सेल और सेवायोजन कार्यालय की ओर से रोजगार मेले का आयोजन किया गया। मेले में एचआर, सेल ऑफिसर, टेली-ऑफिसर, तकनीक आदि पदों के लिए बीएससी, बीए आदि अभ्यर्थियों की भीड़ पहुंची। मेले में 738 अभ्यर्थियों शामिल हुए। इनमें नौकरी के लिए सिर्फ 337 का चयन हुआ।

बतौर मुख्य अतिथि मेले का उद्घाटन क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी प्रो. संध्या रानी शाक्य, क्षेत्रीय सेवायोजन विभाग के सहायक निदेशक त्रिभुवन सिंह, बरेली कॉलेज के प्राचार्य प्रो. ओपी राय, उग्र उद्योग व्यापार मंडल के प्रदेश महामंत्री राजेंद्र गुप्ता, करियर काउंसलिंग एवं प्लेसमेंट सेल के संयोजक डॉ. राजीव यादव ने संयुक्त रूप से किया। मेले में 15 कंपनियों ने प्रतिभाग किया। बरेली कॉलेज के



सामान्य पाठ्यक्रमों में शामिल बीए, बीएससी के साथ-साथ व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के विद्यार्थियों के साक्षात्कार के बाद 337 अभ्यार्थियों का चयन हुआ।

राजेंद्र गुप्ता ने कहा कि व्यापार मंडल के माध्यम से बरेली कॉलेज के छात्र-छात्राओं को स्टार्टअप की

शुरूआत के लिए हरसंभव मदद प्रदान की जाएगी। प्राचार्य प्रो. ओपी राय ने कहा कि शीघ्र ही महाविद्यालय की करियर काउंसलिंग एवं प्लेसमेंट सेल हमारे परिसर में अध्ययन करने वाले छात्र-छात्राओं को बड़े-बड़े इंडस्ट्रीज में इंटरशिप के लिए भेजेगा। सहायक निदेशक

त्रिभुवन सिंह ने विभाग के रोजगार संगम पोर्टल पर पंजीकरण के लिए बच्चों को आमंत्रित किया और कहा कि पोर्टल के माध्यम से बरेली कॉलेज परिसर के छात्र छात्राओं को विदेशों में भी नौकरी के अवसर प्राप्त होंगे।

डॉ. राजीव यादव ने बताया कि बीते चार माह में महाविद्यालय के 100 से अधिक विद्यार्थी निजी सेवा प्रदाताओं के यहां प्लेसमेंट सेल के माध्यम से रोजगार पा चुके हैं। कार्यक्रम में प्रो. पूनम सिंह, प्रो. आलोक खरे, प्रो. राजेंद्र सिंह, प्रो. एसी त्रिपाठी, प्रो. एमबी कलहंस, डॉ. बीनम सक्सेना, डॉ. नीरज मलिक, डॉ. अरविंद गंगवार, डॉ. अंकुर श्रीवास्तव, संजय कुमार, डॉ. संजय यादव, सेवायोजन कार्यालय के वीरेंद्र कुमार, अनूप दुबे, आशीष कुमार मिश्रा, रामऔतार, अनिल कुमार, राजेश सक्सेना, बृजेश आदि मौजूद रहे।

संपादकीय

वृद्धि में नैसर्गिक न्याय का तकाजा

समिवार को जारी संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा एक गजट नोटिफिकेशन के अनुसार सरकार ने लोकसभा और राज्यसभा सांसदों के वेतन, भत्तों एवं पेंशन में एक अप्रैल 2023 से बढ़ोतरी की है। अब सांसदों का वेतन एक लाख से बढ़कर 1.24 लाख रुपये प्रतिमाह हो जाएगा। साथ ही दैनिक भत्ता दो हजार से ढाई हजार रुपये प्रतिदिन हो जाएगा। वहीं पूर्व सांसदों की पेंशन भी पच्चीस हजार से बढ़कर 31 हजार प्रतिमाह हो जाएगी। इसके साथ ही पांच साल से अधिक की सेवा के लिये सांसदों की अतिरिक्त पेंशन दो हजार से बढ़कर ढाई हजार रुपये हो जाएगी। उल्लेखनीय है कि इससे पहले सांसदों के वेतन व भत्तों में बदलाव अप्रैल 2018 में किया गया था। तर्क दिया जा रहा है कि माननीयों के वेतन में वृद्धि महंगाई और जीवन यापन की बढ़ती लागत के मद्देनजर की गई है। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2018 के परिवर्तन के अनुसार सांसदों को अपने क्षेत्र में ऑफिस चलाने और लोगों से मिलने-जुलने हेतु सत्तर हजार रुपये का भत्ता भी मिलता है। इसके अतिरिक्त उन्हें कार्यालय के व्यय हेतु साठ हजार रुपये महीना और संसद सत्र के दौरान हर दिन दो हजार रुपये का भत्ता भी मिलता है। कहा जा रहा है कि अब इन भत्तों में भी बढ़ोतरी होगी। उल्लेखनीय है कि माननीयों को हर साल फोन व इंटरनेट हेतु भत्ता, अपने परिवार के लिये 34 फ्री डोमेस्टिक फ्लाइट, निजी यात्रा के लिये रेल में प्रथम श्रेणी में यात्रा सुविधा, सड़क मार्ग से चलने पर ईंधन का खर्च व मुफ्त बिजली झ्र पानी की सुविधा भी मिलती है। इसके अलावा सरकारी व निजी अस्पतालों में मुफ्त चिकित्सा सुविधा भी उपलब्ध करायी जाती है। यदि किसी रोग का भारत में पर्याप्त इलाज संभव न हो तो सरकार विशेष स्थिति में विदेश में उपचार के खर्च की अनुमति दे सकती है। साथ ही सरकारी आवास की सुविधा और यदि आवास न लें तो घर का भत्ता माननीयों को मिलता है।

वहीं सरकार की दलील है कि वेतन-भत्तों में यह 24 फीसदी की वृद्धि लागत मुद्रास्फीति सूचकांक के आधार पर ही की गई है। दरअसल, सरकार ने अपने पिछले कार्यकाल में सांसदों के वेतन और भत्तों की हर पांच साल में समीक्षा करने का जो नियम बनाया था, उसका निर्धारण समय की महंगाई दर के आधार पर किया जाना था। निस्संदेह, लोकतंत्र के नीति-नियंताओं का जीवन विशिष्ट सुविधाओं का आकांक्षी होता है। वहीं सुख-सुविधाओं में वृद्धि तार्किकता की भी मांग करती है। यह नैसर्गिक न्याय ही होगा, यदि राजा और प्रजा के जीवन में समृद्धि की बयार समान रूप से होती है। इसमें अधिक अंतर भी न हो। किसी भी लोकतांत्रिक समाज में जनता का, जनता द्वारा और जनता के लिये के नारे का यथार्थ में फलीभूत होना भी जरूरी है। अभिजात्य संस्कृति की तार्किकता लोकतंत्र की कसौटी पर खरी नहीं उतरती। किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में प्रश्न आयकरदाता के धन के सदुपयोग व उसकी उत्पादकता का भी है। जिसके जरिये विसंगतियां दूर करने व असमानता की खाई पाटने की तार्किकता भी शामिल है। हम यह न भूलें कि महंगाई का दंश देश की आम प्रजा भी भुगत रही है। नीति-नियंताओं को उसके कष्ट दूर करने के लिये संवेदनशील ढंग से सोचना चाहिए। आम लोगों को सामाजिक सुरक्षा का कवच देने के मुद्दे को भी प्राथमिक बनाया जाना चाहिए। करोड़ों लोगों को सस्ती व गुणवत्ता की चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना भी हमारी प्राथमिकता बननी चाहिए। यह भी यक्ष प्रश्न कि देश की आजादी के साढ़े सात दशक बाद भी हमें अस्सी करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज देने को क्यों बाध्य होना पड़ रहा है। सार्वजनिक विमर्श में यह मुद्दा भी अकसर उठता रहा है कि जिस व्यवस्था की जनप्रतिनिधि संस्थाओं में करोड़पति जनप्रतिनिधियों का वर्चस्व हो, उनके लिये वेतन, भत्ते और पेंशन की तार्किकता क्या है? वहीं दूसरी ओर राजनीतिक विमर्श में नई-पुरानी पेंशन की आकांक्षा में चिंतित जनमानस को देशव्यापी एकरूपता के साथ विकल्प दिये जाने की भी जरूरत है। ताकि तेजी से उपद्राज लोगों का देश होते भारत में करोड़ों लोगों का बुढ़ापा सुखमय हो सके। ताकि सुख, समृद्धि व सुकून राजा के घर भी हो और प्रजा के भी।

मुस्लिम तुष्टिकरण के

लिये कांग्रेस सरकारें

अपने-अपने राज्यों में

अतिशयोक्तिपूर्ण

घोषणाएं एवं योजनाएं

लागू करती रही हैं,

कर्नाटक में भी वहां

के मुख्यमंत्री

सिद्धरमैया ने सरकार

का बजट पेश करते

हुए मुस्लिमों के लिए

कई घोषणाएं की।

सीएम ने एलान किया

कि सार्वजनिक निर्माण

अनुबंधों में से 4

प्रतिशत अब श्रेणी-ए

बी के तहत

मुसलमानों के लिए

आरक्षित होंगे। सरकार

ने कहा कि मुस्लिम

लड़कियों के लिए 15

महिला कॉलेज खोले

जाएंगे। इसका निर्माण

वक्फ बोर्ड की ही

जमीन पर किया

जाएगा, लेकिन

सरकार इस पर पैसा

खर्च करेगी। मौलवियों

को 6000 मासिक

भत्ता देने की भी

व्यवस्था इस बजट में

की गई है। कर्नाटक

सरकार के बजट में

दलितों और पिछड़ों के

कल्याण के लिए

समुचित बजट आवंटित

नहीं हुआ लेकिन

मुस्लिम तुष्टिकरण के

चलते मुस्लिमों के

लिये लुभावना बजट

आवंटित किया गया

कांग्रेस एक बार फिर संविधान को लेकर विवादों से घिर गयी है। संविधान के संबंध में कांग्रेस का दोहरा रवैया एवं चरित्र एक बार फिर देश के सामने आया है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी अक्सर हाथ में संविधान की प्रति लेकर भाजपा पर इसे बदलने का आरोप लगाते रहे हैं। लोकसभा चुनाव के समय अपनी हर सभा में इस आरोप को दोहराते रहे कि अगर भाजपा फिर से सत्ता में आई तो संविधान बदल कर आरक्षण खत्म कर देगी, इसका भाजपा को नुकसान भी उठाना पड़ा है, लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि भाजपा पर संविधान बदलने का आरोप लगाने वाली कांग्रेस आज खुद संविधान बदलने की बात कर रही हैं। दरअसल, कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार ओबीसी कोटा के तहत पिछड़े मुस्लिमों को आरक्षण देने जा रही है, सार्वजनिक निर्माण अनुबंधों में मुसलमानों को 4 प्रतिशत आरक्षण के संदर्भ में जब उप- मुख्यमंत्री डी के शिवकुमार को यह याद दिलाया गया कि संविधान के तहत मजहब के आधार पर आरक्षण देना मुमकिन नहीं है, तब उन्होंने इशारा किया कि आरक्षण देने के लिए जरूरी बदलाव किए जाएंगे। शिवकुमार के इस बयान के बाद कर्नाटक से लेकर दिल्ली तक फिर संविधान बचाने का सियासी अभियान हावी हो गया है। इस बार भाजपा आक्रामक है और उसने फिलहाल इसे एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बना दिया है। इस वर्ष बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव का यह अहम मुद्दा बन जाये तो कोई आश्चर्य नहीं है। मुस्लिम तुष्टिकरण के लिये कांग्रेस सरकारें अपने-अपने राज्यों में अतिशयोक्तिपूर्ण घोषणाएं एवं योजनाएं लागू करती रही हैं, कर्नाटक में भी वहां का निर्माण अनुबंधों में से 4 प्रतिशत अब श्रेणी-ए बी के तहत मुसलमानों के लिए आरक्षित होंगे। सरकार ने कहा कि



मुस्लिम लड़कियों के लिए 15 महिला कॉलेज खोले जाएंगे। इसका निर्माण वक्फ बोर्ड की ही जमीन पर किया जाएगा, लेकिन सरकार इस पर पैसा खर्च करेगी। मौलवियों को 6000 मासिक भत्ता देने की भी व्यवस्था इस बजट में की गई है। कर्नाटक सरकार के बजट में दलितों और पिछड़ों के कल्याण के लिए समुचित बजट आवंटित नहीं हुआ लेकिन मुस्लिम तुष्टिकरण के चलते मुस्लिमों के लिये लुभावना बजट आवंटित किया गया है। जबकि सरकारों का काम किसी धर्म एवं समुदाय विशेष का तुष्टिकरण न होकर सभी समुदायों का पुष्टीकरण होना चाहिए। जब संविधान में धर्म आधारित आरक्षण का निषेध किया गया है तो फिर जानबूझकर कर्नाटक में कांग्रेस सरकार द्वारा इसे सूचीबद्ध करके विधि सम्मत क्यों बनाया जा रहा है? दरअसल, भाजपा और कांग्रेस, दोनों देश की प्रमुख पार्टियों को यह एहसास हो चला है कि संविधान इस देश में बहुत संवेदनशील विषय है और इस पर लोग कतई समझौता नहीं करेंगे। संविधान केवल न्यायिक या वैधानिक दस्तावेज नहीं है, बल्कि वह भारत की जनता की आशाओं एवं आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करता है। इस अर्थ में यह देश के जन-जन के मन का दस्तावेज है। संविधान भारत में सभी नागरिकों के लिए दिग्दर्शक तत्व है। इसलिए, प्रश्न यह उठता है कि जब संविधान इतना स्पष्ट है तो क्या संविधान की मूल भावना पर केवल राजनीतिक स्वार्थ के लिए आघात करना स्वस्थ लोकतंत्र का लक्षण है?

दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस पवित्र ग्रंथ पर भी विपक्षी दल एवं कांग्रेस अत्यंत निकृष्ट राजनीति करती जा रही है। जो कांग्रेस शासन में रहते हुए कभी संविधान का सम्मान नहीं कर सकी, वह आज विपक्ष में बैठकर यह भ्रम फैलाने में लगी है कि मोदी सरकार संविधान को खत्म कर देगी। सच तो यह है कि कांग्रेस जैसे दल आज अपने मूल राजनीतिक विचार को खो बैठे हैं। कांग्रेस अपने गांधीवादी विचार और समाजवादी पार्टी जैसे दल समाजवाद और राम मनोहर लोहिया के मूलभूत विचारों को भूल चुके हैं। संविधान को आधार बनाकर विपक्षी दल जनता को विभाजित करने, मुस्लिम तुष्टिकरण एवं राजनीतिक स्वार्थ की रेटियां सेंकने बाज नहीं आ रहे हैं। आश्चर्य नहीं, कांग्रेस ने संविधान को लेकर जो हथियार चलाया था, वही हथियार कर्नाटक में स्वयं कांग्रेस के विरुद्ध चला गया है। अब इससे होने वाले नुकसान का भान होते ही कांग्रेस तत्काल बचाव में लग गई। वैसे, शिवकुमार के स्पष्टीकरण के बावजूद भाजपा इस मुद्दे पर निशाना साध रही है, तो संकेत साफ है, वह सियासत का मौका जाने नहीं देना चाहेगी। वह संविधान बदलने और न बदलने पर फिर से गर्म हुई राजनीति को ठंडा नहीं होने देगी। बीते लोकसभा चुनाव में जहां भाजपा निशाने पर थी, वहीं इस बार कांग्रेस निशाने पर आ गई है। लोकसभा-राज्यसभा में एवं इस वर्ष बिहार में होने वाले चुनावों में भाजपा कांग्रेस पर आक्रामक रहेगी। अब तो तीर कमान से निकल चुका है, भले ही अब

कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री शिवकुमार सफाई देने में लगे हैं कि उनके बयान को तोड़-मरोड़कर पेश किया गया और वह संविधान में बदलाव का प्रस्ताव कभी नहीं रखेंगे। स्पष्ट है कि हमारा संविधान धर्म के आधार पर आरक्षण का पक्षधर नहीं है। डॉ. भीमराव अंबेडकर भी ऐसे आरक्षण के हिमायती नहीं थे। संविधान सभा में एकमत के साथ यह तय हुआ था कि धर्म के आधार पर कोई आरक्षण नहीं दिया जाएगा। अब अगर ऐसे आरक्षण की जरूरत पड़ने लगी है, या कांग्रेस मुसलमानों के वोट बैंक को अपने पक्ष में करने के लिये आरक्षण का हथियार चलाती है तो संविधान में संशोधन तो करना ही होगा। अपने आजाद देश में जरूरतमंदों को आरक्षण देने के लिए करीब 12 बार संविधान में संशोधन किए गए हैं और मुस्लिमों को महज मजहबी बुनियाद पर आरक्षण देने के लिए भी ऐसी जरूरत पड़ेगी।

गांधी परिवार के अत्यंत करीबी कर्नाटक के डिप्टी सीएम के बयान को सुनकर लोग हैरत में हैं। लोग संविधान के खिलाफ धर्म के आधार पर आरक्षण देने की कांग्रेस की कोशिश का विरोध कर रहे हैं। धर्म के आधार पर मुस्लिम आरक्षण के मुद्दे पर भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी ने कर्नाटक में संविधान की धज्जियां उड़ा दी है। कांग्रेस मुस्लिम तुष्टिकरण के लिये देश को दांव पर लगाती रही है। एक बार फिर उसकी इस कोशिश से उसका असली चेहरा देश के सामने आया है। कांग्रेस भारत के संविधान के साथ खिलवाड़ कर रही हैं, मुस्लिम आरक्षण को संविधान

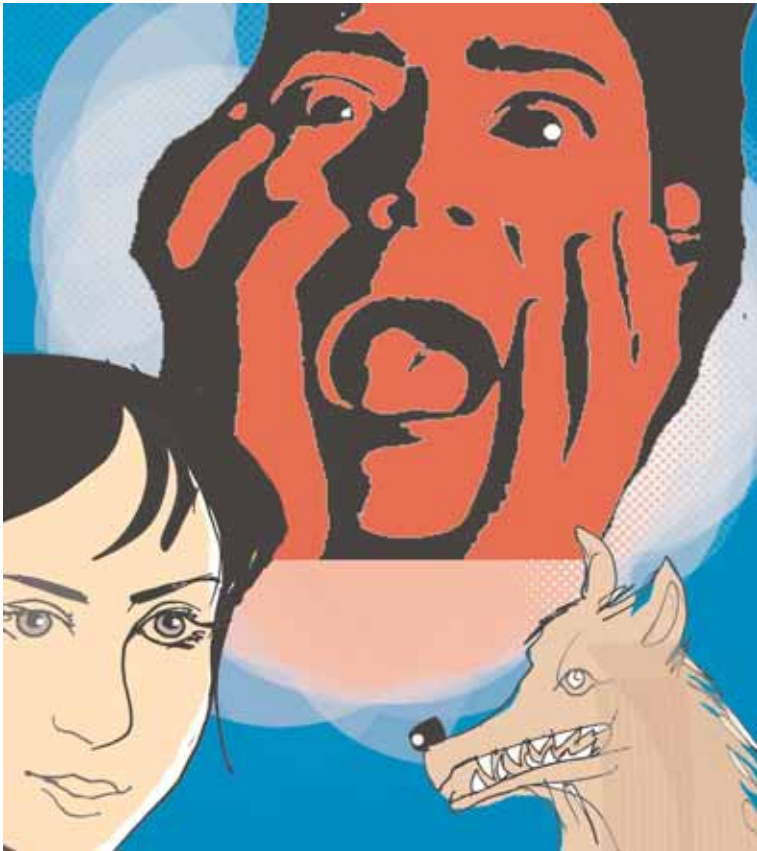
में जगह देकर संविधान निमाता बाबा साहेब अंबेडकर के खिलाफत की जा रही है। मुस्लिमों को आरक्षण असंवैधानिक हैं। कांग्रेस बार-बार मुस्लिम आरक्षण की वकालत कर संविधान की मूल भावना को चुनौती दे रही है। मुस्लिम वोटबैंक के लिए ऐसा किया जाना संविधान की मूल भावना से खिलवाड़ है। राहुल गांधी एवं कांग्रेस पार्टी का रवैया आरक्षण को लेकर समय-समय पर बदलता रहा है। कभी उसने संविधान संशोधन की बात की, तो कभी आरक्षण का विरोध किया, तो कभी धर्म के आधार पर आरक्षण देने के प्रयास भी किए। आपातकाल के काले दौर में कांग्रेस द्वारा ऐसा भी किया गया, जब इंदिरा गांधी सरकार ने संविधान की मूल प्रस्तावना ही बदल डाली। कांग्रेस नेता संविधान की किताब जेब में रखते हैं, लेकिन इसे कमजोर करने के लिए हरसंभव कोशिश भी करते हैं। अब कांग्रेस अध्यक्ष को पार्टी की स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए और देश को बताना चाहिए कि कांग्रेस मुसलमानों को आरक्षण देने के लिए संविधान में बदलाव क्यों करना चाहती है?

कांग्रेस का रवैया हर प्रकार से संविधान विरोधी ही रहा है। संविधान को कमजोर करने वाले अनेक प्रयास कांग्रेस समय-समय पर करती आई है। कांग्रेस द्वारा अपने शासनकाल में इस पर संशोधन लाने का प्रयास किया गया कि सरकार संविधान में क्या-क्या परिवर्तन कर सकती है? स्पष्ट है कि कांग्रेस के लिए हमारा संविधान केवल सत्ता को साधने का एक उपकरण मात्र रहा है, संविधान के प्रति सम्मान की भावना कांग्रेस के चरित्र में नहीं है। जबकि वर्ष 2014 में सत्तारूढ़ होने के बाद से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की सरकार संविधान के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की संकल्पना को पूरा करने के लिए प्रयासरत है। भारतीय संविधान और लोकतंत्र को सुदृढ़ करने की मंशा से प्रधानमंत्री मोदी द्वारा अनेक कदम उठाए गए हैं।

पॉक्सो एक्ट और महिलाओं की सुरक्षा पर सवाल, कोर्ट के फैसले पर चर्चा

सरकार को भी मौजूदा कानूनों की समीक्षा करनी चाहिए ताकि इस प्रकार की विवादास्पद व्याख्याओं की कोई गुंजाइश न रहे और यौन अपराधों के पीड़ितों को न्याय मिल सके। बीते दिनों इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा सुनाया गया एक फैसला महिलाओं की सुरक्षा के संबंध में एक गंभीर बहस का केंद्र बन गया है। यह निर्णय ऐसे समय में आया है जब देश में महिलाओं के विरुद्ध अपराधों की संख्या चिंताजनक रूप से बढ़ रही है। इसके प्रति कानूनी समुदाय व नागरिक समाज में तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति राम मनोहर नारायण मिश्र ने कासगंज जिले के एक मामले में कहा कि किसी महिला के स्तनों को पकड़ना, उसके पायजामे की डोरी तोड़ना और उसे पुलिया के नीचे खींचने का प्रयास करना बलात्कार या बलात्कार के प्रयास की श्रेणी में नहीं आता है। यह फैसला पॉक्सो एक्ट के तहत 11 साल की पीड़िता से जुड़े मामले में सुनाया गया था। न्यायाधीश ने बलात्कार के प्रयास के आरोप को खारिज करते हुए, इसे भारतीय दंड संहिता की धारा 354-बी के तहत ह्रस्व उतारने के इरादे से हमलाह और पॉक्सो एक्ट की धारा 9/10 के तहत ह्रगंभीर यौन हमलाह

माना। न्यायालय का मानना है कि इस मामले में किए गए कृत्य बलात्कार के प्रयास की कानूनी परिभाषा की पूरी तरह से संतुष्ट नहीं करते हैं, लेकिन गंभीर यौन हमले की श्रेणी में आते हैं। इस निर्णय के कानूनी विश्लेषण पर विचार करें तो, यह स्पष्ट होता है कि न्यायालय ने अपराध की तैयारी और वास्तविक प्रयास के बीच स्थापित कानूनी सिद्धांत का पालन करने का प्रयास किया है। भारतीय दंड संहिता के तहत, किसी भी अपराध के लिए केवल प्रयास ही दंडनीय है, जबकि केवल तैयारी को अपराध नहीं माना जाता है। इसके अतिरिक्त, न्यायालय ने आरोपियों के खिलाफ पॉक्सो एक्ट की धारा 9/10 के तहत गंभीर यौन हमला के अपराध को बरकरार रखा है, जो यह दर्शाता है कि न्यायालय ने कथित अपराध की गंभीरता को पूरी तरह से अनदेखा नहीं किया है। कुछ कानूनी विशेषज्ञ यह तर्क दे सकते हैं कि न्यायालय का कर्तव्य कानून को उसके अक्षरों के अनुसार लागू करना है, भले ही इसके सामाजिक परिणाम विवादास्पद क्यों न हों। उल्लेखनीय है कि सर्वोच्च न्यायालय ने पहले के कई निर्णयों में यौन इरादे से किसी नाबालिग के अंगों को छूने को भी यौन हमला माना है। 19 नवंबर, 2021 के सर्वोच्च न्यायालय के फैसले में बॉम्बे हाईकोर्ट



के नागपुर पीठ के एक फैसले को पलटते हुए यह स्पष्ट रूप से कहा गया था कि किसी नाबालिग के यौन अंगों को छूना या यौन इरादे से शारीरिक संपर्क से जुड़ा कोई भी कृत्य पॉक्सो एक्ट की धारा 7 के तहत यौन हमला माना जाएगा, जिसमें इरादे को प्रमुखता

दी गई थी। इस फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने रिक्कन से रिक्कन संपर्क की आवश्यकता से अधिक यौन इरादे को महत्व दिया था। इलाहाबाद उच्च न्यायालय का वर्तमान निर्णय इस पूर्ववर्ती फैसले से स्पष्ट रूप से भिन्न प्रतीत होता है।

मध्य प्रदेश सरकार बनाम महेन्द्र उर्फ गोलू के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने बलात्कार के प्रयास के आरोपी की दोषसिद्धि को बरकरार रखते हुए तैयारी और प्रयास के बीच का अंतर समझाया था, जिसमें यह माना गया था कि अभियुक्त के कृत्य तैयारी से आगे बढ़कर अपराध के निकट थे। इलाहाबाद उच्च न्यायालय का निर्णय इस व्याख्या से भी कुछ हद तक भिन्न प्रतीत होता है। इस अदालती निर्णय का मौजूदा कानूनों पर संभावित प्रभाव भी महत्वपूर्ण है। पॉक्सो एक्ट के संदर्भ में, इस निर्णय से बच्चों को यौन अपराधों से सुरक्षा प्रदान करने के अधिनियम के मूल उद्देश्य पर ही सवाल उठ सकते हैं। यदि इस प्रकार के कृत्यों को बलात्कार के प्रयास के रूप में नहीं माना जाता है, तो यह कानून के प्रभावी कार्यान्वयन को कमजोर कर सकता है। इसी प्रकार, यह निर्णय आईपीसी की धारा 376 (बलात्कार) और धारा 354 (शील भंग करने के इरादे से हमला) के बीच की रेखा को भी धुंधला कर सकता है, खासकर जब यौन उत्पीड़न की गंभीरता का आकलन किया जा रहा हो, परिणामस्वरूप पॉक्सो एक्ट के तहत यौन अपराधों की एक संकुचित व्याख्या हो सकती है, जिससे बच्चों की सुरक्षा का कानूनी ढांचा कमजोर

हो सकता है। इस न्यायिक फैसले के सामाजिक-राजनीतिक परिणाम व्यापक हो सकते हैं। इससे समाज में महिलाओं की सुरक्षा के प्रति गलत संदेश जा सकता है, जिससे यौन अपराधों को गंभीरता से न लेने की प्रवृत्ति बढ़ सकती है। इससे महिला अधिकार कार्यकर्ताओं और नागरिक समाज समूहों के विरोध के सुर मजबूत हो सकते हैं। राजनीतिक स्तर पर, मौजूदा कानूनों में संशोधन या नए कानून बनाने की मांग उठ सकती है, ताकि कानूनी अस्पष्टताओं को दूर किया जा सके और महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। सार्वजनिक विमर्श में मांग उठी है कि सर्वोच्च न्यायालय को इस मामले में हस्तक्षेप करना चाहिए ताकि कानूनी स्पष्टता बनी रहे और महिलाओं तथा बच्चों के अधिकारों की प्रभावी ढंग से रक्षा की जा सके। इसके अतिरिक्त, सरकार को भी मौजूदा कानूनों की समीक्षा करनी चाहिए ताकि इस प्रकार की विवादास्पद व्याख्याओं की कोई गुंजाइश न रहे और यौन अपराधों के पीड़ितों को न्याय मिल सके। यह अनिवार्य है कि एक मजबूत कानूनी ढांचा स्थापित किया जाए जो महिलाओं और बच्चों को यौन हिंसा से प्रभावी ढंग से बचा सके।

कांशीराम के पैटर्न पर लौटीं मायावती, लंबे अरसे बाद पार्टी चलाएगी कोई अभियान; रिश्तेदारों को तवज्जो नहीं

नेशनल प्रेस टाइम ब्यूरो

लखनऊ। अपने रिश्तेदारों को पार्टी से दूर करने के बाद मायावती बदले अंदाज में राजनीति करती नजर आ रही हैं। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि वह कांशीराम के पैटर्न पर चल पड़ी हैं। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने संगठन को एकजुट करने तथा पार्टी का जनाधार बढ़ाने के लिए ओबीसी समाज को जोड़ने की मुहिम चलाने की शुरुआत कर कार्यकर्ताओं को नया संदेश दिया है। बसपा के संस्थापक कांशीराम की तर्ज पर उन्होंने इस बार अपने परिजनों को दरकिनार करते हुए पार्टी कैडर को प्राथमिकता दी है। जानकारों की मानें तो बसपा द्वारा ओबीसी समाज को जोड़ने के लिए गांव-गांव चलाया जाने वाले अभियान



से पार्टी को नई ऊर्जा मिल सकती है। बता दें कि बीते करीब दो साल से बसपा तमाम उठापटक से जूझ रही है। बसपा सुप्रिमो द्वारा आकाश आनंद को अपना उत्तराधिकारी बनाने के बाद दो बार हटाने के निर्णय से कार्यकर्ताओं का मनोबल टूटा, जिसका असर तमाम चुनावों में देखने को मिला। बसपा सुप्रिमो ने पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी

और आकाश के ससुर अशोक सिद्धार्थ को भी पार्टी से बाहर कर दिया। साथ ही, भविष्य में पार्टी से जुड़े अहम फैसलों में नाते-रिश्तों की परवाह नहीं करने का रास्ता चुना। इसका प्रभाव हालिया ओबीसी समाज की विशेष बैठक में भी देखने को मिला, जिसमें बसपा सुप्रिमो ने केवल पार्टी कैडर के समर्पित पदाधिकारियों और

कार्यकर्ताओं को बुलाया और उन्हें अहम जिम्मेदारियां सौंपी। उन्होंने यह भी कहा कि जो पार्टी के प्रति समर्पित होकर कार्य करेगा, भविष्य में उसे ही आगे बढ़ाया जाएगा।

लंबे अर्से के बाद कोई अभियान

बसपा ने लंबे अर्से के बाद कोई अभियान शुरू करने की घोषणा की है। दरअसल, पार्टी के कैडर कैंपों के आयोजन के बावजूद जनाधार बढ़ने की जगह कम होता जा रहा था। पार्टी नेता कैडर कैंप आयोजित करके अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ रहे थे। अब गांव-गांव अभियान चलाने से बसपा का बिखरा वोट बैंक फिर से संगठित हो सकता है। इसमें युवाओं को खास तवज्जो दी जाएगी, ताकि नई पीढ़ी को तैयार किया जा सके। बसपा सुप्रिमो ने खासकर महिलाओं को इस अभियान में शामिल करने का निर्देश भी दिया है।

प्रदेश के शिक्षक-कर्मचारियों को 30 मार्च के पहले मिल जाएगा इस माह का वेतन? सीएम योगी को लिखा गया पत्र

लखनऊ। यूपी के शिक्षक और कर्मचारियों को मार्च माह का वेतन 30 मार्च के पहले देने की मां की गई है। कर्मचारी संगठनों ने इसको लेकर सीएम को पत्र लिखा है।

विशिष्ट बीटीसी शिक्षक वेल्फेयर एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र भेजकर 30 मार्च से पहले प्रदेश के शिक्षकों-कर्मचारियों को वेतन दिए जाने की मांग की है। संघ के प्रांतीय अध्यक्ष संतोष तिवारी ने कहा है कि 30 मार्च से चैत्र नवरात्र शुरू हो रहा है। वहीं 31 मार्च या एक अप्रैल को ईद पड़ रही है। संगठन के प्रांतीय सचिव दिलीप चौहान ने कहा दोनों ही त्यौहार हिंदू व मुस्लिम समाज के लिए महत्वपूर्ण हैं। ऐसे में प्रदेश के लाखों शिक्षक-कर्मचारियों को मार्च का वेतन इसी सप्ताह देने के लिए आदेश किया जाए। उन्होंने यह भी बताया है कि पूर्व में परिषदीय विद्यालयों में जुमा, अलविदा का अवकाश होता रहा है। पूर्व की भांति अलविदा पर



भी छुट्टी घोषित की जाए। शिक्षक/कर्मचारियों को इसका लाभ मिल सके। यूपी: परिषदीय स्कूलों के छात्र सीखेंगे ब्रज, अवधी, बुंदेली और भोजपुरी, व्जंजनों के बारे में दी जाएगी जानकारी

शिक्षकों-कर्मचारियों को ईद से पहले करें वेतन का भुगतान

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ (चंदेल गुट) ने प्रदेश सरकार से मांग की है कि शिक्षक-कर्मचारियों को ईद के पहले वेतन भुगतान किया जाए। साथ ही 31 मार्च को ईद को देखते हुए बोर्ड परीक्षा मूल्यांकन कार्य बंद किया जाए। संघ के प्रदेश मंत्री संजय द्विवेदी ने मुख्यमंत्री

योगी आदित्यनाथ को भेजे पत्र में कहा है कि ईद 31 मार्च को है। सरकार की वित्तीय नियमावली के अनुसार माह की आखिरी तारीख पर पड़ने वाले अवकाश व पूर्व के हटित एडवांस में वेतन भुगतान किया जा सकता है। पूर्व में भी ऐसा किया गया है। ऐसे में ईद को ध्यान में रखते हुए सरकार कर्मचारियों को एडवांस में वेतन भुगतान करें। द्विवेदी ने कहा कि यूपी बोर्ड की कॉपीयों का मूल्यांकन 19 मार्च से शुरू हुआ है, जो दो अप्रैल तक चलेगा। ईद के हटित 31 मार्च को प्रदेश के सभी मूल्यांकन केंद्रों पर मूल्यांकन कार्य स्थगित करने के निर्देश जारी किए जाएं।

एमएफ मंत्रा: म्यूचुअल फंड के साथ सीखें सफल निवेशक बनने के गुर, एक्सपर्ट आज देंगे जानकारी

लखनऊ। म्यूचुअल फंड के साथ-साथ लक्ष्य आधारित निवेश कैसे हो? बेहतर पूंजी निवेश कहाँ की जाए? निवेश की चुनौतियों व हर अवसर की जानकारी आपको देने के लिए अमर उजाला ला रहा है एमएफ मंत्रा कार्यक्रम। जहाँ मार्केट के दिग्गज मिरे एसेट के नॉर्थ सेल्स रीजनल हेड मुकेश कुमार और फार्नेशियल मार्केट एक्सपर्ट व मोटिवेशनल स्पीकर डॉ विशाल सक्सेना



आपको निवेश के सटीक मंत्र बताएंगे।

27 मार्च को निरालानगर रोड स्थित होटल रेगेंट में अमर उजाला की ओर से आयोजित हो रहे जागरूकता

नए अवसरों, पूंजी को सुरक्षित रखने और नुकसान की कम से कम गुंजाइश के टिप्स भी मिले।

यही नहीं, विशेषज्ञ निवेशकों के सवालों का जवाब भी देंगे। कार्यक्रम में आमजन भी भागीदार बनकर शेयर मार्केट और म्यूचुअल फंड में बेहतर निवेश सीख

सकते हैं। म्यूचुअल फंड बाजार के जोखिमों के अधीन है इसलिए योजना से जुड़े सभी कार्यक्रम के बारे में जानकारी के लिए मोबाइल नंबर 8858900080 पर संपर्क कर सकते हैं। कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए क्यूआर कोड स्कैन कर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं।

वृन्दावन के भगवान रंगनाथ मेले में मारपीट, कुर्सियां फेंकीं

मथुरा। वृंदावन में भगवान रंगनाथ के दस दिवसीय मेले (ब्रह्मोत्सव) में सोमवार को मामूली विवाद में 2 गुटों में मारपीट हुई। बात बढ़ने पर कुर्सियां तक फेंकी गईं इस कारण मेले में भगदड़ मच गई। मामले में पुलिस ने दो लोगों का पकड़ कर उनका शांति भंग में चालान कर दिया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, अचानक झगड़ा इतना बढ़ गया कि कई श्रद्धालु डर के मारे इधर-उधर भागने लगे। करीब आधा घंटा तक विवाद हुआ, तब कहीं जाकर पुलिस आई। पुलिस ने दो लोगों को मौके से दबोच लिया। थाना प्रभारी ने बताया कि गौरा नगर निवासी मनीष और कृष्ण उर्फ कान्हा का चालान किया गया है। मेले के दौरान कई मेले में प्रवेश कर गई। जिस कारण जाम की स्थिति बनी रही। चुंगी चौराहे पर मेला कमेटी के मंच से गाड़ियों को न लाने का अनाउंस करते रहे।

आईजीआरएस में रैंक हो गई कम, इसलिए मांट थाना प्रभारी पर गिरी गाज, लाइन हाजिर

मथुरा के मांट में मुख्यमंत्री की आईजीआरएस(एकिकृत शिकायत निवारण प्रणाली) में जनपद की रैंक कम आने पर एसएसपी ने बड़ा कदम उठाया है। मांट थाना प्रभारी को लाइन हाजिर कर दिया गया है। इस कार्रवाई से अधीनस्थों के हड़कंप मचा हुआ है। शिकायतों का निस्तारण न करने पर मांट थाना प्रभारी निरीक्षक राजीत वर्मा को तत्काल प्रभाव से लाइन हाजिर कर दिया है। बताया जा रहा की जनपद की रैंक शिकायतों के निस्तारण में मांट थाने की वजह से कम आई थी, जिसकी वजह से एसएसपी नाराज थे। मंगलवार को विवेचनाओ को लेकर ओआर(अर्दली रूम) में भी मांट प्रभारी निरीक्षक पहुंचे नहीं थे। एसएसपी ने फिलहाल किसी को थाना मांट का चार्ज नहीं दिया है।



फोर लेन मार्ग पर डिवाइडर निर्माण की मांग को लेकर, किसानों ने लोक निर्माण विभाग कार्यालय का किया घेराव



एनपीटी ब्यूरो

मथुरा। भारतीय किसान यूनियन भानु के गुस्साए सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रीय प्रवक्ता हरेश ठेनुआ और जिलाध्यक्ष देवेन्द्र पहलवान के साथ आज कृष्णापुरी चौराहे पर स्थित लोक निर्माण विभाग कार्यालय का यमुना एक्सप्रेस-वे से वृंदावन को जोड़ने वाले फोर लेन मार्ग पर डिवाइडर और नाली निर्माण की मांग को लेकर कार्यालय का घेराव कर नारेबाजी की। जिसके बाद किसान डिवाइडर बनाए

जाने की मांग को लेकर अधिकारियों का घेराव कर कार्यालय के अंदर फर्श पर बैठ गए। जहां भारतीय किसान यूनियन भानु के राष्ट्रीय प्रवक्ता हरेश ठेनुआ और जिलाध्यक्ष देवेन्द्र पहलवान ने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों पर यमुना एक्सप्रेस-वे के फोर लेन मार्ग पर पानीगांव के पास डिवाइडर न बनाने और रिश्तव व दलाली लेकर काम करने का आरोप लगाते हुए लोक निर्माण विभाग कार्यालय मथुरा का करीब एक घंटे

तक घेराव किया। जहां अधिशासी अभियन्ता गुलवीर सिंह को फोर लेन मार्ग पर डिवाइडर के निर्माण को लेकर अवगत कराया। जिस पर अधिशासी अभियन्ता गुलवीर सिंह ने एक हफ्ते में समस्या का समाधान करने का आश्वासन दिया। तब जाकर किसान शांत हुए। वहीं कार्यालय का घेराव करने में महानगर अध्यक्ष विजय सिंघल, जगदीश रावत राष्ट्रीय सचिव, गिर्राज सिंह, भूरा पहलवान प्रदेश अध्यक्ष प्रकोष्ठ, लक्ष्मीनारायण जिला महासचिव, विक्रम सिंह चौधरी, सुरेन्द्र चौधरी कार्यकर्ता, कुशलपाल चौधरी, अमरसिंह, भूरा चौधरी, मानसिंह चौधरी, रामबीर सिंह, जितेन्द्र चौधरी आदि आक्रोशित कार्यकर्ता शामिल रहे।

बीएसए कार्यालय में रिश्तव लेने के आरोपी की जमानत पर टली सुनवाई

एनपीटी ब्यूरो

मथुरा। बीएसए कार्यालय मथुरा में तैनात वरिष्ठ सहायक ब्रजराज सिंह को एंटी करप्शन आगरा की टीम ने 25 हजार रुपये की रिश्तव लेने के आरोप में 19 जून 2024 के रंग हाथ गिरफ्तार किया था। यह रिश्तव सदर बाजार निवासी धर्मेन्द्र सिंह से उनके पिता रामेश्वर सिंह की अनिवार्य सेवानिवृत्ति का नोटिस समाप्त करने के एवज में ली गई थी। वह रामेश्वर सिंह कन्या जूनियर हाईस्कूल वृंदावन में परिचारक के पद पर तैनात हैं। हाईकोर्ट में जमानत पर सुनवाई हुई। इस दौरान सरकार का पक्ष रखते हुए शासकीय अधिवक्ता ने



मामले के सह आरोपी बीएसए सुनील दत्त की जांच की वर्तमान स्थिति की जानकारी करने के लिए एक सप्ताह का समय मांगा है। इसके बाद भी उन्होंने सुनवाई की मांग की। इस पर हाईकोर्ट ने एक सप्ताह का समय देते हुए मुकदमे को 1 अप्रैल 2025 को सूचीबद्ध करने के आदेश दिए हैं। रिश्तव लेने के आरोप में वरिष्ठ सहायक ब्रजराज सिंह

की गिरफ्तारी के बाद बीएसए ने भी भ्रष्टाचार निवारण न्यायालय मेरठ में अग्रिम जमानत के लिए 8 जुलाई 2024 को अर्जी दाखिल की थी। लगातार तीन माह तक कई बार सुनवाई हुई, लेकिन हर बार बीएसए के अधिवक्ता ने अगली तारीख मांगी। इस पर न्यायालय ने 30 सितंबर 2024 को अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी थी।

शिक्षक भर्ती: 69 हजार शिक्षक भर्ती: SC में सुनवाई न होने से अभ्यर्थियों में आक्रोश, शिक्षा मंत्री का आवास घेरकर किया हंगामा

एनपीटी ब्यूरो

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में 69 हजार शिक्षक भर्ती में शामिल आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों ने सोमवार को बेसिक शिक्षा मंत्री के आवास का घेराव किया।

उत्तर प्रदेश में 69 हजार शिक्षक भर्ती में शामिल आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों ने सोमवार को बेसिक शिक्षा मंत्री के आवास का घेराव किया। अभ्यर्थियों ने नारेबाजी करते हुए जमकर हंगामा किया। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची है।

नारेबाजी कर रहे अभ्यर्थियों ने कहा कि 69 हजार शिक्षक भर्ती में काफी अनियमितता हुई है। इस कारण



आरक्षित वर्ग के हजारों अभ्यर्थी नौकरी पाने से वंचित रह गए हैं। मामले में हाईकोर्ट ने उनके पक्ष में फैसला सुनाया। लेकिन सरकार की लापरवाही के कारण उसका पालन नहीं हुआ। अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट में है।

प्रदर्शन कर रहे अमरेंद्र पटेल ने बताया कि वर्ष 2018 में यह भर्ती प्रक्रिया शुरू हुई थी। जब इसका परिणाम आया तो इसमें आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के साथ अन्याय किया गया। उन्हें नौकरी देने से वंचित कर दिया गया। लंबे आंदोलन और

न्यायिक प्रक्रिया से गुजरने के बाद 13 अगस्त 2024 को लखनऊ हाईकोर्ट की डबल बेंच ने आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के हित में फैसला सुनाया।

हाईकोर्ट ने नियमों का पालन करते हुए तीन महीने के अंदर अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने का आदेश दिया। लेकिन, सरकार इस प्रकरण में हीला हवाली करती रही। मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया। सुप्रीम कोर्ट में भी सरकार लापरवाही कर रही है। इस कारण हम लोगों को सड़क पर उतरना पड़ा है। हमारी मांग है कि सरकार सुप्रीम कोर्ट में हमारी मजबूत पैरवी करे। हमें जल्द न्याय दिलाए।

प्रदेश सरकार के सेवा, सुरक्षा व सुशासन के 8 वर्ष पूर्ण होने पर तीन दिवसीय मेले का हुआ आगाज, प्रभारी मंत्री ने फीता काटकर किया उद्घाटन

सूचना विभाग द्वारा 8 वर्ष की उपलब्धियों पर आधारित विकास पुस्तिका का किया विमोचन



एनपीटी ब्यूरो ललितपुर ललितपुर। प्रदेश सरकार के सेवा, सुरक्षा व सुशासन की नीति के 8 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर आयोजित तीन दिवसीय मेले का आज मा0 राज्यमंत्री, अल्पसंख्यक कल्याण, मुस्लिम वक्फ एवं हज एवं जनपद प्रभारी मंत्री श्री दानिश आजाद अंसारी ने कल्याण सिंह सभागार (ऑडिटोरियम) में रिविन काटकर उद्घाटन किया। इस अवसर पर मा0 सदर विधायक रामरतन कुशवाहा, मा0 जिला पंचायत अध्यक्ष कैलाश नारायण निरंजन, जिलाध्यक्ष भाजपा हरीश रावत, मा0 सदस्या उ0प्र0 राज्य महिला आयोग अर्चना पटेल, मा0 राज्यमंत्री प्रतिनिधि चन्द्रशेखर पंथ, सांसद प्रतिनिधि अनिल पटैरिया, राजकुमार जैन, जिलाधिकारी अक्षय त्रिपाठी, पुलिस अधीक्षक मो0 मुरताक, मुख्य विकास अधिकारी कमलाकांत पाण्डेय आदि की गरिमामयी उपस्थिति रही।

कल्याण सिंह ऑडिटोरियम के परिसर में मा0 प्रभारी मंत्री सहित सभी जनप्रतिनिधियों व अधिकारियों ने जनपद में विगत 8 वर्षों में किये गए विकास कार्यों व योजनाओं के विभागीय स्टॉल व चित्र प्रदर्शनी का अवलोकन किया और उनकी प्रशंसा की। इस दौरान मा० मंत्री जी ने अपने

सम्बोधन में कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन और मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के मिशन को आत्मसात करते हुए वर्ष 2017 में डबल इंजन की सरकार ने सुरक्षा, सुशासन और विकास की जिस यात्रा को प्रारंभ किया था, वह आज नए भारत के नए उत्तर प्रदेश के रूप में पूरे देश के समक्ष एक मॉडल के रूप में प्रस्तुत हुई है। आप सभी इसके साक्षी और सहभागी रहे हैं। हमारी नीतियों के प्रति जिस प्रकार जनता ने अपना सहयोग और समर्थन दिया है, उससे यह विश्वास और दृढ़ हो चला है कि स्पष्ट नीति, साफ नीयत, प्रतिबद्धतापूर्ण नियोजन के सदप्रयास सुफलित अवश्य होते हैं। उत्तर प्रदेश के ट्रांसफॉर्मेशन की चर्चा आज राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय मंचों पर हो रही है। इस सकारात्मक बदलाव के पीछे ट्रिपल सी यानी कल्चर, कनेक्टिविटी और कॉमर्स का मंत्र है। कानून व्यवस्था में सुधार आम जन को सम्मानजनक जीवन को गारंटी देता है, साथ ही छोटे- बड़े हर निवेशक हर व्यापारी को निवेश की सुरक्षा की गारंटी सुनिश्चित करवाता है। बेहतर इन्फ्रास्ट्रक्चर भी आम जनों के जीवन को बेहतर बनाने के साथ ही निवेशकों को कम लागत अधिक उत्पादन और बेहतर रिजल्ट की गारंटी देता है। ये दोनों पक्ष मिलकर पूरे प्रदेश के सामाजिक और आर्थिक परिवेश में क्रांतिकारी बदलाव ला रहे हैं। जिसमें उत्तर प्रदेश को आर्थिक विकास में ऊंचे पायपदान पर पहुंचाया है। डबल इंजन सरकार ने ळ्लिख के मूलमंत्र के महत्व को समझते हुये इसके सभी पक्षों को अपनी नीतियों के केंद्र में रखा है।

कलैक्ट्रेट सभागार:-

कल्याण सिंह ऑडिटोरियम कार्यक्रम के उपरान्त मा० प्रभारी मंत्री जी ने मीडिया बंधुओं के साथ पत्रकार वार्ता कर ललितपुर के सकारात्मक विकास पर चर्चा करते हुए मीडिया के द्वारा ललितपुर के उठाई गई समस्याओं के निराकरण के लिए मौक पर ही अधिकारियों को निर्देश दिये।

इसके बाद मा० प्रभारी मंत्री जी ने कलेक्ट्रेट सभागार में सी०एम०डैश बोर्ड पर विभिन्न योजनाओं की जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ विकास कार्यों की समीक्षा बैठक की। बैठक में बताया गया कि विकास कार्यों की रैंकिंग में ललितपुर का प्रदेश में 6वां स्थान है, जिस पर मा0 प्रभारी मंत्री ने प्रसन्ता जाहिर करते हुए अधिकारियों को और अधिक उत्साह से कार्य करने के लिए प्रेरित किया।

उन्होंने एक-एक कर जनपद के विकास कार्यों की प्रगति एवं प्रदेश में रैंकिंग की समीक्षा की और अधिकारियों को निर्देशित किया कि किसी भी दशा में विकास कार्यों में लापरवाही नहीं होनी चाहिए, निमाणांधीन कार्यों को तेजी से गुणवत्ता के साथ पूर्ण कराया जाए तथा जनप्रतिनिधियों के द्वारा बतायी गई समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर समाधान कराया जाए।

मा0 प्रभारी मंत्री ने कहा कि जनपद में मंदिर, मस्जिद या विद्यालयों के आसपास शराब की दुकानें नहीं होनी चाहिए, उन्होंने जिला आबकारी अधिकारी को निर्देशित किया कि एक सप्ताह के अंदर ऐसी सभी शराब की दुकानों को चिन्हित कर उन्हें अन्य स्थान पर शिफ्ट कराकर रिपोर्ट उपलब्ध करावें।

राज्य महिला आयोग की सदस्य अर्चना पटेल ने दिलाया जीजीआईसी की शिक्षिकाओं व कंप्यूटर ऑपरेटर का महीना से रुका मानदेय

एनपीटी ब्यूरो ललितपुर ललितपुर राजकीय बालिका इंटर कॉलेज की शिक्षिकाओ व कंप्यूटर ऑपरेटर का करीब 5 माह से मानदेय न मिलने पर सभी परेशान थे पर जब मामला राज्य महिला आयोग की सदस्य अर्चना पटेल के पास पहुंचा तो उन्होंने तुरंत ही जिला विद्यालय निरीक्षक को आदेश किया कि सभी शिक्षिकाओ व कंप्यूटर ऑपरेटर का मानदेय जल्द से जल्द दिया जाए उसके बाद सभी को मानदेय मिलने के बाद शिक्षिकाओ व कंप्यूटर ऑपरेटर में खुशी की लहर दिखाई दी जिससे राजकीय बालिका इंटर कॉलेज की कंप्यूटर ऑपरेटर सुनना पंथ ने आज राज्य महिला आयोग की सदस्य अर्चना पटेल जी को फूल माला पहनाकर आभार व धन्यवाद व्यक्त किया जिसमें राज्य महिला आयोग की सदस्य अर्चना पटेल ने कहा कि महिलाओं की परेशानी मेरी परेशानी है कोई भी हमारी माताएं बहने परेशान नहीं रहे ऐसी हमारी सरकार की मंशा है और मैं सभी हमारी माताओ बहनों को न्याय दिलाने में हमेशा उन सभी के साथ हूं।

मंदिर के समीप खुलीं शराब की दुकानें हटवायी जाए : हरपाल सिंह सिसोदिया प्रभारी मंत्री दानिश अंसारी को सौंपा ज्ञापन



एनपीटी ब्यूरो ललितपुर ललितपुर बार- भाजपा मंडल अध्यक्ष हरपाल सिंह सिसोदिया ने मंगलवार को ललितपुर आए प्रभारी मंत्री दानिश अंसारी को पत्र सौंपकर कस्बा बार के बस स्टैंड पर खुलीं शराब दुकानों से लोगों को हो रही परेशानियों से अवगत कराकर शराब की दुकानें हटवाने की मांग की है।

उन्होंने अवगत कराया है कि कस्बा बार में बस स्टैंड पर देशी, अंग्रेजी शराब व बियर की दुकान खुली हुई हैं। इन दुकानों से 30 मीटर दूर प्रसिद्ध मां विंध्यवासिनी शक्ति पीठ मंदिर व वियर की दुकान के सामने माता शबरी मंदिर स्थित है, जहां प्रतिदिन सैकड़ों लोग दर्शन को आते हैं। बताया कि आबादी क्षेत्र में बस स्टैंड पर

शराब की दुकानें होने के कारण आये दिन स्थानीय लोगों, यात्रियों व मंदिर आने-जाने वाली महिलाओं को काफी परेशानी होती है। बस स्टैंड पर शराबियों का उत्पात मचा रहता है। इस सम्बन्ध में पहले भी कई बार शराब की दुकान हटवाये जाने हेतु कस्बावासियों व उन्होंने जिला प्रशासन को पत्र के माध्यम से अवगत कराया जा चुका है लेकिन उपरोक्त दुकानें न तो हटवायी गयी हैं और न ही स्थान परिवर्तित किया गया है जिससे कस्बावासियों में रोष व्याप्त है। एक अप्रैल से नए सिरे से आवंटित दुकानों का संचालन होना है जिस कही भी अन्य जगह संचालित कराया जाये।

पुलिस विभाग ने रैली निकालकर नगरवासियों को किया जागरूक गैस रिसाव से लगीं आग में झुलसी मां बेटी

चित्रकूट ब्यूरो: उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार की सेवा, सुरक्षा व सुशासनद्व न नीति के आठ वर्षह पूर्ण होने के अवसर पर जिला मुख्यालय में पुलिस विभाग के मिशन शक्ति, यूपी 112, महिला पीआरवी, अग्निशमन टीम द्वारा निकाली गई सरकार के महत्वपूर्ण कार्यों एवं कल्याणकारी परियोजनाओं से सम्बन्धित जागरूकता रैली को पुलिस अधीक्षक अरुण कुमार सिंह ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया।

जागरूकता रैली में सर्वप्रथम मिशन शक्ति अभियान के क्रम में कार व स्कूटी पर महिला आरक्षियों ने महिलाओं व बालिकाओं के प्रति होने वाले अपराध के सम्बन्ध में जागरूकता का संदेश दिया। साथ ही डायल 112 की पुलिस टीम ने आपातकालीन समय पर पुलिस की मदद के लिए



डायल 112 का प्रयोग करने का संदेश दिया। इसके अलावा जनता के बीच जाकर पुलिस द्वारा उनके सहयोग के लिए चलाये जा रहे हूऑपरेशन कन्विक्शनह्क की जानकारी दी। बताया कि इसमें पुलिस द्वारा चिन्हित अभियोगों में प्रभावी पैरवी कराकर अपराधियों को सजा दिलाई जाती है। इसी प्रकार हूऑपरेशन दृष्टिह्क के माध्यम से जनपद के समस्त थानों के चैराहों, बाजारों एवं मिश्रित आबादी क्षेत्रों में सीसीटीवी कैमरें लगाये गये है, जिससे अपराध पर प्रभावी अंकुश लगाने में मदद मिलगी।

ललितपुर बार- कस्बा बार के बानपुर रोड निवासी महिला गैस जलाते समय आग की चपेट में आ गई साथ में खड़ी छोटी बेटी भी झुलस गई। परिजन उन्हें लेकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर गए जहां हालत गंभीर होने पर जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया।

कस्बा निवासी दीपमाला (28वर्ष) पत्नी संजय नामदेव सोमवार सुबह चाय बनाने के लिए गई जहां गैस चूल्हा जलाते ही कमरे में आग लग गई। उक्त महिला आग की चपेट में आ गई साथ में खड़ी उसकी पांच वर्षीय बेटी जयंती भी झुलस गई। चीख पुकार करने पर परिजन पहुंचे भारी मशक्कत के बाद मां बेटी को बाहर निकालकर उन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर गए जहां महिला की हालत गंभीर होने पर उन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। परिजनों का कहना है कि रविवार शाम को ही नया सिलेंडर लगाया था, गैस रिसाव के कारण यह हादसा हुआ। महिला की चार लड़कियां हैं, जिनमें जयंती तीसरे नंबर की बेटी है।

विद्यार्थियों को बांटे रामायण ज्ञान परीक्षा प्रमाण पत्र प्रभारी मंत्री ने ली कानून व्यवस्था व विकास कार्यों की समीक्षा बैठक



चित्रकूट ब्यूरो: विश्व हिंदू परिषद प्रखंड मऊ के सरस्वती विद्या मंदिर में रामायण ज्ञान परीक्षा प्रमाण पत्र वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। साथ ही मासिक बैठक कर आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा निर्धारित की गई। कार्यक्रम का शुभारंभ श्रीराम दरबार एवं भारत माता के चित्र पर माल्यार्पण व द्वीप प्रज्वलित कर किया गया। विश्व हिंदू परिषद के जिलाध्यक्ष राजेंद्र त्रिवेदी ने बताया कि कार्यक्रम में रामायण परीक्षा में प्रतिभाग करने वाले विद्यार्थियों को प्रमाण पत्र का वितरण किया गया है। इस मौके जिला मंत्री नीरज केशरवानी, विश्व हिन्दू परिषद के मऊ मंत्री संदीप श्रीवास्तव मऊ प्रखंड के संरक्षक मुकेश वाजपेई, मंत्री संदीप श्रीवास्तव, सह मंत्री अंकित शुक्ला, संयोजक शिवांक केशरवानी सहित समस्त प्रखंड के कार्यकर्ता आदि मौजूद रहे। कार्यक्रम के बाद आयोजित की गई प्रखंड की मासिक बैठक में संगठन के पदाधिकारियों ने आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा निर्धारित की गई।

चित्रकूट ब्यूरो: जनपद के प्रभारी मंत्री मनोहर लाल (मन्नु कोरी) की अध्यक्षता में सीएम डैशबोर्ड के माध्यम से कानून व्यवस्था एवं विकास कार्यों की समीक्षा बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित की गई। जिसमें मंत्री ने कानून व्यवस्था व विकास कार्यों की समीक्षा कर सम्बन्धित दिशा-निर्देश दिए।

बैठक में मंत्री ने कानून व्यवस्था की समीक्षा करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री योगी का प्रमुख उद्देश्य कानून व्यवस्था बनाए रखना है। गुंडे-बदमाश जेल के बाहर नहीं रहने चाहिए उन्हें जेल की सलाखों में ही रखें। पुलिस अधीक्षक अरुण कुमार सिंह ने बताया कि जनपद में कानून व्यवस्था सामान्य है।



मिशन के अंतर्गत ग्रामीणों द्वारा की गई शिकायतों पर कहा कि बरहट में योजना के तहत पानी नहीं पहुंचाया जा रहा। जिस पर अधिशासी अभियंता जल निगम ने बताया कि सम्बन्धित ग्राम पंचायत में अवशेष कार्य पूरा होते ही पानी की सप्लाई कर दी जाएगी। आईजीआरएस के संबंध में कहा कि प्राप्त शिकायतों का निस्तारण त्वरित व गुणवत्तापूर्ण होना चाहिए। तुलसीदास

शासन की गाइडलाइन के अनुसार शहरी व ग्रामीण क्षेत्र में बिजली सप्लाई करें। मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी ने बताया कि जनपद की 305 गौशालाओं में 55 हजार गौवंश संरक्षित किए गए हैं। मंत्री समय से चरवाहों का भुगतान करने के निर्देश दिए।

मंत्री ने उपस्थित सभी अधिकारियों को पात्र लाभार्थी को योजनाओं का लाभ दिलाने के निर्देश दिए। कहा कि सरकारी नदों में जो भी लापरवाही करेगा, उनके खिलाफ जिलाधिकारी के माध्यम से कार्रवाई कराई जाएगी।

इस मौके पर भाजपा जिलाध्यक्ष महेन्द्र कोटावई, जिला सहकारी बैंक अध्यक्ष पंकज अग्रवाल, नगर पंचायत अध्यक्ष राजापुर संजीव मिश्रा, भाजपा जिला महामंत्री आलोक पांडेय,

जिलाधिकारी शिवशरणप्पा जीएन, मुख्य विकास अधिकारी अमृतपाल कौर, अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व उमेश चंद्र निगम, मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ भूपेश द्विवेदी, परियोजना निदेशक सच्चिदानंद प्रसाद, डीसी एनआरएलएम ओपी मिश्रा, डीसी मनरेगा धर्मजीत सिंह, जिला बेसिक शिक्षाधिकारी बीके शर्मा, जिला आबकारी अधिकारी अखिलेंद्र प्रताप सिंह, जिला समाज कल्याण अधिकारी ज्ञानेंद्र सिंह भदौरिया, जिला प्रोबेशन अधिकारी पंकज मिश्रा, जिला पंचायत राज अधिकारी इंद्र नारायण सिंह, जिला कार्यक्रम अधिकारी पीडी विश्वकर्मा सहित सम्बन्धित अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे।

नवलगढ़ के खिरोड़ में शहीद हवलदार रामजी लाल कटेवा की मूर्ति अनावरण सभा में शहीदों की पार्थिव देह उनके घर तक पहुंचाने का काम वाजपेयी जी ने किया.... उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी

नेशनल प्रेस टाइम ब्यूरो

झुंझुनूं। प्रदेश की उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी ने झुंझुनूं जिले के नवलगढ़ तहसील के खिरोड़ में शहीद हवलदार रामजी लाल कटेवा की मूर्ति के अनावरण समारोह में बतौर मुख्य अतिथि हिस्सा लिया। उन्होंने शहीद कटेवा की मूर्ति पर पुष्पांजली अर्पित करते हुए मुर्ति का अनावरण किया। इस मौके पर आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी ने शहीदों के बलिदान को अमूल्य बताया। उन्होंने देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को याद करते हुए कहा कि वाजपेयी ने शहीदों की पार्थिव देह को शहीदों के घर तक पहुंचाने का कार्य शुरू किया था। दिया कुमारी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सैनिक कल्याण के क्षेत्र में ह्रावन रैंक, वन पेंशनह्न शुरू करने के लिए आभार जताते हुए विगत 11 वर्षों में देश में सैनिक कल्याण और सुरक्षा व्यवस्था के क्षेत्र में हुए कार्यों की भी जानकारी आमजन को दी। उन्होंने



कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मंगलवार को बाड़मेर में आयोजित सभा में 30 हजार से अधिक संख्या में महिलाएं आईं जो बड़ी बात है। इस मौके पर उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी ने क्षेत्र के शहीदों की वीरांगनाओं का भी सम्मान किया। सभा में नवलगढ़ विधायक विक्रम सिंह जाखल ने नौजवानों को देश के प्रति समर्पित होकर कार्य करने की बात कही। उन्होंने विभिन्न विकास कार्यों के लिए औ? जनसभा में आने के लिए दिया कुमारी का आभार व्यक्त किया। सभा

को खंडेला विधायक सुभाष मील ने भी संबोधित किया। कार्यक्रम में मंच पर शहीद कटेवा की वीरांगना प्रभाती देवी, पूर्व विधायक रतन जलधारी, नगरपालिकाध्यक्ष सुरेंद्र सैनी फूलवाला, सरपंच महावीर सिंह भांबू, पंचायत समिति सदस्या जानकी देवी मौजूद रही। मंच संचालन एडीईओ उम्मेद सिंह महला और विजय हिंद जालिमपुरा ने किया। इससे पहले उपमुख्यमंत्री का नांगल समेत उदयपुरवाटी क्षेत्र के विभिन्न गांवों में आमजन और कार्यकर्ताओं ने

महेंद्र चंदवा के नेतृत्व में स्वागत किया। जिन्होंने देश के लिए इतना कुछ दिया, उसके आगे सड़क क्या है.. उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी* उपमुख्यमंत्री ने नवलगढ़ विधायक विक्रम सिंह जाखल और शहीद के परिजनों की मांग को स्वीकार करते हुए तुर्किनी जोहड़ से कैमरी की ढाणी तक 5 किलोमीटर सड़क निर्माण शहीद कटेवा के नाम से करने की घोषणा की। उन्होंने घोषणा के बाद कहा कि शहीद कटेवा ने जो देश के लिए योगदान दिया है, जो बलिदान दिया है, उसके आगे यह सड़क क्या है?

नवलगढ़ में करवाए गए विकास कार्य भी बताए
उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी ने कहा कि लोहार्गल के बरखंडी में रोप वे का कार्य शुरू हो रहा है। वहीं नवलगढ़ में ट्रोमा सेंटर, जिला अस्पताल, 90 करोड़ से अधिक की सड़कों की सौगत दी गई है।

फार्मर रजिस्ट्री में 81.92% के साथ जिला प्रदेश में दूसरे स्थान पर, इतने किसानों ने कराया पंजीयन
सिरोही- केन्द्र सरकार की एग्रीस्टैक योजना के तहत फार्मर रजिस्ट्री शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। जिले में 65,965 पीएम किसान लाभार्थियों के विरुद्ध 54,069 किसानों का पंजीकरण अब तक किया जा चुका है।

जिला कलक्टर ने किया शहर का दौरा

जिला अस्पताल में चल रहे विकास कार्यों, जैतसागर नाले के निर्माण की प्रगति एवं खेल संकुल के साथ ही अन्य विकास कार्यों का किया निरीक्षण

ब्युरो -एनपीटी

बूंदी, 26 मार्च। जिला कलक्टर अक्षय गोदारा ने बुधवार को बूंदी शहर का दौरा किया। उन्होंने जैतसागर नाले के निर्माण की प्रगति देखी और खेल संकुल में व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। उन्होंने नगर परिषद के नव निर्मित भवन का अवलोकन कर आवश्यक जानकारी ली एवं जिला अस्पताल में चल रहे विकास कार्यों के साथ ही नवल सागर झील का भी निरीक्षण किया। जिला कलक्टर ने मीरां गेट व महावीर कॉलोनी क्षेत्र में हो रहे जैतसागर नाले के निर्माण की प्रगति देखी और संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि निर्माण कार्य में लगी टीमों की संख्या बढ़ाकर निर्माण कार्य में गति

लाएं। उन्होंने कहा कि मानसून से पहले नाले के निर्माण का कार्य पूर्ण कर लिया जाए, ताकि आमजन को किसी तरह की परेशानी ना हो। साथ ही कार्य में गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाए। उन्होंने खेल संकुल परिसर में संचालित तरणताल का निरीक्षण कर अधिकारियों को निर्देश दिए कि तरणताल का अधिकाधिक प्रचार-प्रसार विभिन्न माध्यमों से किया जावें ताकि आमजन को गर्मियों में इसकी सुविधा का लाभ मिल सके। उन्होंने कहा कि वर्तमान में निमाणांधीन मल्टीपरपज हॉल के कार्यों में गुणवत्ता का ध्यान रखते हुए गति बढ़ाई जावें एवं साफ-सफाई पर विशेष ध्यान दिया जावें। उन्होंने कुंभा स्टेडियम



के पास नगर परिषद के नवनिर्मित भवन का अवलोकन किया और वर्तमान में पूर्ण हो चुके कार्यों के बारे में जानकारी ली। इसके अलावा टाउन हॉल के निर्माण कार्य में प्रगति लाने के निर्देश दिए। उन्होंने चितौड़ रोड़ पर चल रहे सीवरेज कार्य का भी निरीक्षण किया। उन्होंने निर्देश दिए कि

सीवरेज कनेक्शनों की संख्या बढ़ाई जावें साथ ही सभी निर्माण कार्य तय समय सीमा में पूर्ण कर लिए जावें। जिला कलक्टर ने पर्यटन को बढ़ावा देने के दृष्टिगत नवल सागर झील पर कराए जा रहे सौंदर्यीकरण के कार्यों का भी निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने निर्देश दिए कि झील पर पुराने रोप-वे के

ढाचें को व्यवस्थित रूप से दूसरी जगह पर स्थानांतरित किया जावें।

उन्होंने जिला अस्पताल परिसर में निमाणांधीन नवीन ब्लॉक के कार्यों का निरीक्षण करते हुए संबंधित अधिकारी को निर्देश दिए कि श्रमिकों की संख्या बढ़ाकर कार्य शीघ्र पूर्ण किया जाए। साथ ही कार्य प्रगति की नियमित मॉनिटरिंग भी की जाए। जिला अस्पताल परिसर में साफ-सफाई पर विशेष ध्यान दिया जावें।

इस दौरान नगर परिषद आयुक्त संतलाल मक्कड, प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉ. प्रभाकर विजय,, आरएसआरडीसी के सहायक अभियंता सुरेंद्र गुर्जर सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।

एक दिवसीय कैम्पस प्लेसमेंट शिविर का हुआ आयोजन

ब्युरो -एनपीटी

बूंदी। राजस्थान दिवस समारोह के कम में रोजगार कार्यालय, बून्दी एवं राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, नैनवा रोड, बून्दी ने कैम्प आयोजित किया गया। कैम्पस प्लेसमेंट शिविर का शुभारम्भ सभापति श्रीमती सरोज अग्रवाल नगर परिषद, बून्दी में मां सरस्वती का दीप प्रचलित कर किया। जिला रोजगार अधिकारी बैंक



प्रकाश नागर ने बताया की इस शिविर में अडानी विल्मोर प्राॅलॅन् बून्दी, जे.डी. एक्स सिक्वोरिटी नोएडा, आल इंडिया जॉब सोल्यूशन कोटा, सहित कुल-05 संस्थानी ने शिविर में भाग लिया। संस्थानों द्वारा नियोजन हेतु-28, एवं प्रशिक्षण हेतु-13 आशार्थियों का प्राथमिक चयन किया गया साथ ही शिविर में उपस्थित

आशार्थियों को स्वरोजगार से सम्बन्धित परामर्श व जानकारी दी गई। शिविर में लगभग 300 आशार्थियों ने भाग लिया। इस अवसर पर आई. टी. आई. उपनिदेशक श्री फूलचन्द मीणा त्तमुह अनुदेशक श्री सज्जाद अली खान, दीपक बाथरा, एवं लोकेश सैनी मौजूद रहे।

राजस्थान दिवस समारोह के दूसरे दिन जिला स्तरीय किसान सम्मेलन का हुआ आयोजन

ब्युरो -एनपीटी

बूंदी, 26 मार्च। राजस्थान दिवस (चैत्र शुक्ल प्रतिपदा, 30 मार्च) के उपलक्ष्य में राज्य सरकार द्वारा वृहद स्तर पर 7 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी श्रृंखला में बुधवार को दूसरे दिन जिला स्तरीय किसान सम्मेलन एवं किसान उत्पादक संगठन मेले का आयोजन बूंदी के सेंटर फॉर एक्सीलेंस के सभागार में किया गया। इस अवसर पर किसानों को राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं में लाभान्वित किया गया। राज्य स्तरीय कार्यक्रम का वीसी के माध्यम से हुआ प्रसारण-बीकानेर में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम का वीसी के माध्यम से जिले में सीधा प्रसारण किया गया। राज्य स्तरीय

कार्यक्रम में मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने 30 हजार किसानों को 137 करोड़ रुपये अनुदान की स्वीकृति राशि का डीबीटी हस्तांतरण एवं किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ) के मेले का शुभारंभ किया। इस के साथ ही पॉली हाउस, सौर पंप, कृषि उपकरण, प्याज भंडारण, मधुमक्खी पालन इत्यादि हेतु 12 योजनाएं, बैल से खेती प्रोत्साहित करने हेतु योजना, किसान सम्मान निधि की राशि में 1000 रुपए की वृद्धि, मंगला पुर बीमा योजना में पशुओं की संख्या दोगुनी, पशुधन स्वास्थ्य हेतु निःशुल्क औषधियों व टीकों की संख्या 138 से बढ़ाकर 200 तथा मुख्यमंत्री थार सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम के दिशा निर्देश भी जारी किए।

राजस्थान दिवस समारोह सप्ताह का दूसरा दिन खैरथल -तिजार जिले के किसानों को मिला विभिन्न योजनाओं का लाभ

नेशनल प्रेस टाइम ब्यूरो

खैरथल तिजारा, 26 मार्च। राजस्थान दिवस समारोह के दूसरे दिन जिला स्तरीय किसान सम्मेलन एवं किसान उत्पादक संगठन मेले का आयोजन जिला सचिवालय के सभागार में किया गया। इस मौके पर जिला स्तरीय कार्यक्रम में जिले के किसानों को राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं से लाभावि्त किया गया।

राज्य स्तरीय कार्यक्रम का वीसी के माध्यम से हुआ सीधा प्रसारण
कार्यक्रम के दौरान बीकानेर में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम का वीसी के माध्यम से सीधा प्रसारण जिला सचिवालय खैरथल-तिजारा के सभागार में किया गया। राज्य स्तरीय किसान सम्मेलन में मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने 30 हजार किसानों को 137 करोड़ रुपये अनुदान की स्वीकृति राशि का डीबीटी हस्तांतरण हुआ **जिले के किसानों को मिला विभिन्न योजनाओं का लाभ**



वित्तीय वर्ष 2024-25 में जिले के 35 किसानों को वर्मी कंपोस्ट इकाई के लिए प्रति कृषक 50 हजार, 147 कृषकों को तारवंदी योजना के लिए प्रति कृषक 40 हजार, खेत तलाई के लिए 32 किसानों को एक लाख बीस हजार, कृषि यंत्रों के लिए 49 किसानों को 18 हजार से एक लाख की राशि, जैविक गोवर्धन योजना के लिए 141 किसानों को 10 हजार प्रति कृषक की राशि का भुगतान प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) के माध्यम से किसानों को किया गया। कार्यक्रम में जिला कलक्टर किशोर कुमार, अतिरिक्त जिला कलक्टर शिवपाल जाट, उपखंड अधिकारी

तिजारा संजीव वर्मा, नगर परिषद आयुक्त मुकेश शर्मा, कृषि विभाग के संयुक्त निदेशक राजेंद्र बसवाल, जिला रसद अधिकारी राकेश सोनी, पशुपालन विभाग के संयुक्त निदेशक हवा सिंह जाट, कोऑपरेटिव विभाग, उद्यान विभाग सहित अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी एवं बड़ी तादाद में किसान मौजूद रहे।

गुरुवार को गरीब एवं अंत्योदय सम्मेलन का होगा आयोजन
राजस्थान दिवस समारोह की कड़ी में जिला स्तरीय गरीब एवं अंत्योदय सम्मेलन का आयोजन गुरुवार को दोपहर 12.00 बजे से किया जाएगा।

जिला कलक्टर ने किया शहर का दौरा

जिला अस्पताल में चल रहे विकास कार्यों, जैतसागर नाले के निर्माण की प्रगति एवं खेल संकुल के साथ ही अन्य विकास कार्यों का किया निरीक्षण

ब्युरो -एनपीटी

बूंदी, 26 मार्च। जिला कलक्टर अक्षय गोदारा ने बुधवार को बूंदी शहर का दौरा किया। उन्होंने जैतसागर नाले के निर्माण की प्रगति देखी और खेल संकुल में व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। उन्होंने नगर परिषद के नव निर्मित भवन का अवलोकन कर आवश्यक जानकारी ली एवं जिला अस्पताल में चल रहे विकास कार्यों के साथ ही नवल सागर झील का भी निरीक्षण किया। जिला कलक्टर ने मीरां गेट व महावीर कॉलोनी क्षेत्र में हो रहे जैतसागर नाले के निर्माण की प्रगति देखी और संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि निर्माण कार्य में लगी टीमों की संख्या बढ़ाकर निर्माण कार्य में गति

लाएं। उन्होंने कहा कि मानसून से पहले नाले के निर्माण का कार्य पूर्ण कर लिया जाए, ताकि आमजन को किसी तरह की परेशानी ना हो। साथ ही कार्य में गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाए। उन्होंने खेल संकुल परिसर में संचालित तरणताल का निरीक्षण कर अधिकारियों को निर्देश दिए कि तरणताल का अधिकाधिक प्रचार-प्रसार विभिन्न माध्यमों से किया जावें ताकि आमजन को गर्मियों में इसकी सुविधा का लाभ मिल सके। उन्होंने कहा कि वर्तमान में निमाणांधीन मल्टीपरपज हॉल के कार्यों में गुणवत्ता का ध्यान रखते हुए गति बढ़ाई जावें एवं साफ-सफाई पर विशेष ध्यान दिया जावें। उन्होंने कुंभा स्टेडियम



के पास नगर परिषद के नवनिर्मित भवन का अवलोकन किया और वर्तमान में पूर्ण हो चुके कार्यों के बारे में जानकारी ली। इसके अलावा टाउन हॉल के निर्माण कार्य में प्रगति लाने के निर्देश दिए। उन्होंने चितौड़ रोड़ पर चल रहे सीवरेज कार्य का भी निरीक्षण किया। उन्होंने निर्देश दिए कि

सीवरेज कनेक्शनों की संख्या बढ़ाई जावें साथ ही सभी निर्माण कार्य तय समय सीमा में पूर्ण कर लिए जावें। जिला कलक्टर ने पर्यटन को बढ़ावा देने के दृष्टिगत नवल सागर झील पर कराए जा रहे सौंदर्यीकरण के कार्यों का भी निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने निर्देश दिए कि झील पर पुराने रोप-वे के

ढाचें को व्यवस्थित रूप से दूसरी जगह पर स्थानांतरित किया जावें।

उन्होंने जिला अस्पताल परिसर में निमाणांधीन नवीन ब्लॉक के कार्यों का निरीक्षण करते हुए संबंधित अधिकारी को निर्देश दिए कि श्रमिकों की संख्या बढ़ाकर कार्य शीघ्र पूर्ण किया जाए। साथ ही कार्य प्रगति की नियमित मॉनिटरिंग भी की जाए। जिला अस्पताल परिसर में साफ-सफाई पर विशेष ध्यान दिया जावें।

इस दौरान नगर परिषद आयुक्त संतलाल मक्कड, प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉ. प्रभाकर विजय,, आरएसआरडीसी के सहायक अभियंता सुरेंद्र गुर्जर सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।

एक साथ 8 सरकारी ट्यूबवैलों का विद्युत कनेक्शन काटने से ग्राम पंचायत किशोरपुरा में मची पानी की त्राहि त्राहि विभागों के चक्कर में फंसी विद्युत बिल की राशि, गांव प्यासा, आखिर जिम्मेदार कौन?

नेशनल प्रेस टाइम ब्यूरो

झुंझुनूं। जिले के उदयपुरवाटी उपखंड क्षेत्र के किशोरपुरा ग्राम पंचायत में बुधवार को विद्युत विभाग द्वारा एक साथ 8 सरकारी ट्यूबवैलों का विद्युत कनेक्शन काट दिया गया। जिससे ग्राम पंचायत किशोरपुरा में पानी की त्राहि त्राहि मची हुई है। ये सरकारी ट्यूबवैल ही ग्राम पंचायत किशोरपुरा की जनता के लिए पीने के पानी का स्रोत थे। ग्रामीणों ने बताया कि गहलोत सरकार के कार्यकाल में बाँडिया नाला क्षेत्र में जल जीवन मिशन योजना के अंतर्गत आठ ट्यूबवैल पीने के पानी के लिए स्वीकृत किए गए थे। जिनसे किशोरपुरा ग्राम पंचायत में पीने के पानी की सप्लाई की जा रही थी। बुधवार को विद्युत विभाग के कर्मचारीयो द्वारा जल जीवन मिशन योजना से जुड़े आठ ट्यूबवैलों का कनेक्शन एक साथ काट दिया गया। जिससे गांव में पानी के लिए त्राहि

त्राहि मची हुई है। विभागों के चक्कर में बिल जमा नहीं होने से पीने के पानी का खामियाजा जनता को भुगतना पड़ रहा हैं। विद्युत विभाग द्वारा कनेक्शन काटे जाने पर ग्रामीणों में आक्रोश की भावना बनी हुई है। ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर और राजस्थान सरकार से मीडिया के माध्यम से मांग कर कहा है कि शीघ्र ही कनेक्शनों को जोड़कर जल सप्लाई चालू की जाए। अन्यथा मजबूरन बड़ा आंदोलन किया जाएगा। मामले की गंभीरता को देखते हुए हमारे संवाददाता ने उदयपुरवाटी उपखंड अधिकारी सुमन सोलन एवं झुंझुनूं जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी रणजीत सिंह से दूरभाष के जरिए संपर्क किया लेकिन उन्होंने फोन नहीं उठाया। **जिम्मेदारों का कहना है-** हमारे विभाग द्वारा पीएचईडी विभाग के अधिकारियो तथा जिला परिषद सीईओ को कनेक्शन काटने से पूर्व

विद्युत बिल की राशि जमा करवाने के नोटिस दिए जा चुके हैं। परंतु उन्होंने बिल जमा नहीं करवाए। मार्च का महीना चल रहा है बिल जमा नहीं होने से कनेक्शन काटे गए हैं। फिर भी इस संबंध में मेरे विभाग के उच्चाधिकारियों से बात करता हूं। **अधीक्षण अभियंता विद्युत विभाग झुंझुनू**
जल जीवन मिशन योजना के अंतर्गत ग्राम पंचायत में गहलोत सरकार में 8 ट्यूबवैल लगाए गए थे। विद्युत विभाग का बिल बकाया चल रहा है। जिसे जमा करवाने के लिए पंचायत के पास कोई फंड नहीं है तथा किसी प्रकार के आधिकारिक आदेश भी नहीं हैं। मैंने इस मामले को लेकर उदयपुरवाटी विकास अधिकारी को अवगत करवाया है। शीघ्र ही जिला कलेक्टर से मिलकर उन्हें मामले से अवगत करवाता हूं। **सरपंच मोहनलाल सैनी ग्राम पंचायत किशोरपुरा-**विद्युत विभाग

के बिल जमा नहीं होने के कारण कनेक्शन काटा गया है। हमारे पास ऐसा कोई फंड तथा आदेश नहीं है जिससे बिल जमा करवाने के लिए ग्राम पंचायत को निर्देशित किया जा सके। विद्युत कनेक्शन ग्राम पंचायत के नाम से नहीं होकर जल एवं स्वच्छता समिति के नाम से हैं। हमने इस मामले को लेकर उच्चाधिकारियों को अवगत करवाया है। इस समस्या का समाधान जयपुर से होगा।

विकास अधिकारी उदयपुरवाटी
बोरवेल जल जीवन मिशन योजना के अंतर्गत लगे हुए हैं। पीएचडी विभाग से इन कनेक्शनों का कोई लेना-देना नहीं है। कनेक्शन ग्राम पंचायत के नाम से हैं। बिल भी ग्राम पंचायत ही जमा करवाए। **अधीक्षण अभियंता पीएचईडी विभाग झुंझुनू**

जिला प्रशासन की पहल पर प्रोजेक्ट जागृति के तहत 24 घंटे खुले रहेंगे दवाई दुकान

एनपीटी ब्यूरो
पाकुड़ (झ़ा॰खं॰), पाकुड़ जिला में अल्प समयावधि में ही अपनी छवि आम जनों के हृदय में समा चुके डीसी मनीष कुमार ने पाकुड़ को संवारने की दिशा में कई महत्वपूर्ण अवयवों को धरातल पर वास्तविक स्वरूप चरितार्थ करने की भूमिका सुनिश्चित करते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने इस दिशा में प्रोजेक्ट परख:- तैयारी उड़ान की, प्रोजेक्ट प्रयास:- हुनर से हौनहार तक का सफर, प्रोजेक्ट प्रारम्भ, प्रोजेक्ट परिवर्तन, प्रोजेक्ट एस॰आई॰पी॰, प्रोजेक्ट आहार, प्रोजेक्ट समावेश, प्रगतिशील पाकुड़

रामनवमी पर्व एवं ईद- उल- फितर त्यौहार को ले पाकुड़ मुफ़र्रिसल थाना में की गई शान्ति समिति की बैठक



एनपीटी ब्यूरो
पाकुड़ (झ़ा॰खं॰), आगामी रामनवमी पर्व, ईद - उल - फितर, सरहुल पर्व अन्य पर्व को ले शान्तिपूर्ण समिति की बैठक अंचल अधिकारी भागीरथ महतो, प्रखण्ड विकास पदाधिकारी समीर अल्ल्रेड मुर्मू व एसडीपीओ डीएन आजाद की संयुक्त अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। बैठक में आगामी त्यौहार यानी रामनवमी पर्व, ईद - उल - फितर, सरहुल एवं अन्य पर्व - त्यौहार को लेकर थाना क्षेत्र से आये उपस्थित गणमान्य व्यक्ति, जनप्रतिनिधिगणों से बारी- बारी से शान्तिपूर्ण माहौल में आपसी भाईचारे के साथ गंगा-यमुनी तहजीब को बरकरार रखते हुए उत्साह के साथ पर्व - त्यौहार मनाने को

विभिन्न धार्मिक त्यौहारों पर शान्ति समिति की बैठक					
क्र.सं.	धार्मिक त्यौहार	प्रकार	स्थिति	प्रकार	स्थिति
1	कनकाच नौचिकाना	बौद्ध	सुनिश्चित	सुनिश्चित	सुनिश्चित
2	दीपावली	हिन्दू	सुनिश्चित	सुनिश्चित	सुनिश्चित
3	गुरुनानक जयन्ती	सिख	सुनिश्चित	सुनिश्चित	सुनिश्चित
4	गुरुनानक जयन्ती	सिख	सुनिश्चित	सुनिश्चित	सुनिश्चित
5	गुरुनानक जयन्ती	सिख	सुनिश्चित	सुनिश्चित	सुनिश्चित
6	गुरुनानक जयन्ती	सिख	सुनिश्चित	सुनिश्चित	सुनिश्चित
7	गुरुनानक जयन्ती	सिख	सुनिश्चित	सुनिश्चित	सुनिश्चित
8	गुरुनानक जयन्ती	सिख	सुनिश्चित	सुनिश्चित	सुनिश्चित
9	गुरुनानक जयन्ती	सिख	सुनिश्चित	सुनिश्चित	सुनिश्चित
10	गुरुनानक जयन्ती	सिख	सुनिश्चित	सुनिश्चित	सुनिश्चित

के साथ - साथ प्रोजेक्ट जागृति (बेहतर स्वास्थ्य की ओर एक कदम) की शुरुआत भी की है। वही पाकुड़ जिले के सर्वसाधारण को बताते हुए खुशी हो रही है कि

प्रोजेक्ट जागृति अन्तर्गत जिला प्रशासन के प्रयास से अब पाकुड़ जिले में भी दवाई दुकान प्रत्येक दिन 24 घंटे खुले रहेंगे। जिला प्रशासन द्वारा 24 घंटे दवाई दुकान खुले नहीं

राष्ट्रीय आविष्कार अभियान के तहत जिला स्तरीय विज प्रतियोगिता सह- विज्ञान प्रदर्शनी का हुआ आयोजन



एनपीटी ब्यूरो
पाकुड़ (झ़ा॰खं॰), झारखण्ड शिक्षा परियोजना पाकुड़ प्रोजेक्ट परख (तैयारी उड़ान की) के तहत राष्ट्रीय आविष्कार अभियान के अन्तर्गत बुधवार को रविन्द्र भवन टाउन हॉल में कक्षा 06 से 08 वीं के छात्रों के लिए जिला स्तरीय विज प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। उपायुक्त मनीष कुमार की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। उपायुक्त मनीष कुमार, विशेष कार्य पदाधिकारी त्रिभुवन कुमार सिंह, जिला शिक्षा पदाधिकारी अनीता पुरती, जिला शिक्षा अधीक्षक नयन कुमार एवं एडीपीओ पीयूष कुमार ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। उपायुक्त मनीष कुमार* ने कहा कि इस कार्यक्रम के माध्यम से सभी बच्चों यहां से जरूर कुछ सीखकर जाएं। उपायुक्त ने कहा कि जल्द ही लाइब्रेरी का निर्माण किया जाएगा। साथ ही उपायुक्त ने बताया कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य बच्चों में विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार के प्रति रुचि जागृत करना और उन्हें नई खोज एवं आविष्कार की दिशा में प्रेरित करना था। इसके अलावा उपायुक्त ने विज्ञान प्रदर्शनी का किया निरीक्षण। उपायुक्त मनीष कुमार, विशेष कार्य पदाधिकारी त्रिभुवन कुमार सिंह, जिला शिक्षा पदाधिकारी अनीता पुरती, जिला शिक्षा अधीक्षक अनीता पुरती ने रविन्द्र भवन में लगाये गये विज्ञान प्रदर्शनी का निरीक्षण किया और छात्रों से विज्ञान प्रदर्शनी से सम्बन्धित जानकारी ली और उनकी कार्यों की सराहना की। उपायुक्त ने सभी विद्यार्थियों को मन लगाकर पढ़ाई करने की अपील की।

हेमन्त सरकार ने आंगनबाड़ी सेविकाओं की दी स्मार्टफोन

एनपीटी ब्यूरो
रांची (झ़ा॰खं॰), झारखण्ड मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन आंगनबाड़ी सेविकाओं और महिला पर्यवेक्षिकाओं एवं अन्य को स्मार्टफोन वितरण कार्यक्रम में शामिल हुए। बुधवार को इस आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने कहा कि आपसे किया हुआ वादा आज निभाया गया है। आज आपको स्मार्टफोन मिला है। वैसे आप में से बहुत लोगों के पास पहले से ही स्मार्टफोन होगा। सरकार की ओर से आज आधिकारिक रूप से आपको

स्मार्टफोन दिया गया है। बदलते समय में जरूरी है कि आप भी तकनीकी रूप से दक्ष हो। इससे आपके केन्द्र में चल रही गतिविधियों को रियल टाइम अपडेट करने में आपको बहुत मदद मिलेगी। साथ ही मॉनिटरिंग में भी यह आपकी सहायता करेगा। तकनीकी रूप से सशक्त होंगी आंगनबाड़ी सेविकाएं और महिला पर्यवेक्षिका। इससे रियल टाइम मॉनिटरिंग सुनिश्चित हो सकेगा। रांची की 100 एवं खूंटी की 50 आंगनबाड़ी सेविकाओं, महिला पर्यवेक्षिकाओं एवं

डटव में कार्यरत कर्मियों को स्मार्ट फोन प्रदान किया गया। अब स्मार्ट फोन का उपयोग कर सरकार, अधिकारियों और स्वास्थ्य कर्मियों से संवाद आसान होगा। मुख्यमन्त्री ने कहा आंगनबाड़ी केन्द्रों की रोजमर्रा के कार्य को आप दर्शा सकती हैं। केन्द्र की गतिविधियों को अपडेट करते रहना है। सरकार द्वारा बताए गये ऐप से कार्य करें एवं निर्देशों के अनुरूप इस मोबाइल का उपयोग करें तो मुझे लगता है, आपकी दिक्कतों का समाधान आसानी से हो सकता है।

भारती एयरटेल फाउंडेशन द्वारा एजुकेशनल रॉकस्टार, एचीवर्स अवार्ड का हुआ आयोजन

एनपीटी ब्यूरो
पाकुड़ (झ़ा॰खं॰), बीते 26 मार्च 2025, पाकुड़, भारती एयरटेल फाउंडेशन, पाकुड़ के द्वारा डाइट भवन पाकुड़ , के सभागार में शैक्षणिक सत्र 2024-25 के लिये एजुकेशनल रॉकस्टार एचीवर्स अवार्ड का आयोजन सफलता पूर्वक सम्पन्न हुआ। इस अवार्ड में पाकुड़ जिले के 2 प्रखण्ड क्रमशः पाकुड़, महेशपुर के 35 विद्यार्थियों से शिक्षकों ने भाग लिया। कार्यक्रम का आयोजन जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के प्राचार्य संतोष गुप्ता के अध्यक्षता में सम्पन्न हुआ। इस कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण शिक्षकों के द्वारा बनाये गये टीएलएम का प्रदर्शन

एवं उसका प्रस्तुतिकरण रहा। सभी शिक्षकों ने एक से बढकर एक टीएलएम के अनुप्रयोग पर अपना प्रस्तुतिकरण दिया। इस अवसर पर निर्वाचक मंडल में राकेश कुमार रजक, विनोद कुमार सिंह, प्रमोद पांडे, भारती एयरटेल फाउंडेशन से अभिषेक

कुमार एवं अरुण कुमार ने शिक्षकों के प्रस्तुतिकरण को गहनता पूर्वक अवलोकन किया। इसके उपरांत अवार्ड के लिये सफलतम प्रीतिभागियो की घोषणा की गई। प्राथमिक विद्यालय श्रेणी के विजेताओं का नाम प्रथम संजय कुमार स्वर्णकार

(उत्कर्मित मध्य विद्यालय लक्ष्मीपुर), द्वितीय जिकेन यादव (उ. म. वि. सुन्दरपहरी) तृतीय दुलाल मंडल (उत्कर्मित मध्य विद्यालय सीतापहारी) तथा उच्च माध्यमिक विद्यालय श्रेणी के विजेताओं के नाम प्रथम प्रमिला कुमारी चौधरी (रानी ज्योतिर्मय गर्ल्स हाई स्कूल पाकुड़), द्वितीय, श्यामल कुमार दास(उत्कर्मित मध्य उच्च विद्यालय गढ़वारी तथा बाबुल अली (पीएम श्री Harindanga+2 high school पाकुड़ है। कार्यक्रम के सफल आयोजन में भारती एयरटेल फाउंडेशन के एकेडमिक मेंटर अरुण कुमार उपाध्याय, अभिषेक कुमार का प्रयास काफी सराहनीय रहा।

मोटरसाइकिल चोरी की वृत्तांत को ले पुलिस ने छह व्यक्ति को धर दबोचा

एनपीटी ब्यूरो
पाकुड़ (झ़ा॰खं॰), मोटरसाइकिल चोरी की वृत्तांत को ले पुलिस ने 6 व्यक्ति को धर दबोचा। दरअसल पुलिस अधीक्षक, पाकुड़ को गुप्त सूचना मिली थी कि पाकुड़ नगर स्थित बस स्टैंड के समीप तीन संदिग्ध व्यक्ति मोटरसाइकिल चोरी करने के फिराक में हैं। सूचना की सत्यापन और आगे की कार्रवाई हेतु पुलिस अधीक्षक, पाकुड़ के निर्देशानुसार एसडीपीओ डीएन आजाद की नेतृत्व में छापेमारी दल का गठन किया गया। साथ ही गठित टीम द्वारा छापेमारी के दौरान पाकुड़ मुफ़र्रिसल थाना क्षेत्र के ग्राम नया योजना से चोरी हुई मोटरसाइकिल का पाटर्स एवं कोयला मोड़ से चोरी के मोटरसाइकिल (लाल रंग का ग्लैमर) के साथ 6 लोगों को रंगे हाथ गिरफ्तार कर नगर थाना कांड संख्या- 89 /2025 विभिन्न सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत प्राथमिकी दर्ज कर अनुसंधान



किया जा रहा है। वही इस कांड में हिरणपुर थाना क्षेत्र समेत पाकुड़ मुफ़र्रिसल थाना एवं अमड़ापाड़ा थाना क्षेत्र के अलावे नगर थाना के भी आपराधिक प्रवृत्ति के लोग शामिल है। एसडीपीओ डीएन आजाद ने बताया कि लगभग 20 वर्षीय जय दे हिरणपुर थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं और वो मंडल कारा, पाकुड़ का कैदी भी रहा है, जो महज 20 दिन पहले ही एक केस से रिहा होकर जेल से बाहर आये थे। साथ ही जय दे की अपराध का पुतना इतिहास भी रहा है। एसडीपीओ डीएन आजाद ने प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि इनके अलावे

पाकुड़ नगर थाना क्षेत्र के 21 वर्षीय अंकित कुमार, अमड़ापाड़ा थाना क्षेत्र के लतीफ अंसारी तथा पाकुड़ मुफ़र्रिसल थाना क्षेत्र के अतिकुर रहमान, सहिबुर रहमान एवं मो॰ मोबाशेर को भी मोटरसाइकिल चोरी की वृत्तांत में गठित छापेमारी टीम के द्वारा विधिवत गिरफ्तार कर लिया गया है। साथ ही चोरी के मोटरसाइकिल का पाटर्स भी बरामद किया गया है। साथ ही चोरी के लाल रंग का ग्लैमर मोटरसाइकिल बिना नंबर प्लेट के भी बरामद किया गया है। वही समाचार लिखे जाने तक पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही थी।

विधायक निशात आलम की ओर से 28 मार्च को आयोजित होगी दावत ए- इफ्तार कार्यक्रम, की अपील



ए- इफ्तार कार्यक्रम का आयोजन 28 मार्च 2025 शुक्रवार को पाकुड़ स्थित रानी ज्योतिर्मय स्टेडियम में किया गया है। झारखण्ड प्रदेश महासचिव तनवीर आलम ने दावत ए- इफ्तार कार्यक्रम की तैयारी को ले स्थलीय (रानी ज्योतिर्मय स्टेडियम का) निरीक्षण कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिया। वही तनवीर आलम ने क्षेत्र के तमाम रोजेदारों समेत महागठबंधन के कार्यकर्ताओं समेत पदाधिकारीगणों को आह्वान करते हुए ससमय अवधि में ही दावत - ए- इफ्तार कार्यक्रम में शिरकत करते हुए दुआ की अपील की है। मौके पर कांग्रेस जिलाध्यक्ष श्रीकुमार सरकार, विधायक प्रतिनिधि गुलाम अहमद, प्रखण्ड अध्यक्ष मानसारल हक, बेलात शेख, नसीम आलम, ए. गंगूली अन्य मौजूद थे।

एनपीटी ब्यूरो
पाकुड़ (झ़ा॰खं॰), तनवीर आलम ने पाकुड़ स्थित रानी ज्योतिर्मय स्टेडियम का दावत ए- इफ्तार कार्यक्रम को ले तैयारी का जायजा लिया। दरअसल झारखण्ड विधानसभा आम निर्वाचन- 2024 में सर्वाधिक मतों से पाकुड़ विधानसभा क्षेत्र से विजय रहे निशात आलम की ओर से दावत

श्री राम कथा का आयोजन का होगा आयोजन

एनपीटी ब्यूरो
रांची, भव्य तरीके से श्री राम कथा का आयोजन 20 अप्रैल से 29 अप्रैल को हाई टेंशन दुर्गा मन्दिर, चुटिया मे आयोजित किया जायेगा । जिसमें मुख्य रुप से लक्ष्मी कुबेर यज्ञ, आयुर्वेद शिविर का भी आयोजन होगा । इस राम कथा में मुख्य कथा वाचक श्री श्री 1008 महात्मा मंडलेशवर ब्राह्मयांड स्वामी पुरी महाराज होंगे । इस सम्बन्ध में 25 मार्च 2025 को श्री राम कथा के भव्य आयोजन की सफलता हेतु महात्मा साईं संजीवनी सेवा की ओर से हाईटेंशन दुर्गा मंदिर में समीर सिंह की अध्यक्षता में एक बैठक का आयोजन किया गया ।

बैठक में राम कथा के भव्य आयोजन की सफलता हेतु नई कमिटि का गठन करने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया और नई कमिटि गठित भी की गई । जिसमें मुख्य रुप से सर्वसम्मति से संयोजक ब्रजेश कुमार,

संरक्षक-मदन सिंह, कैलाश केशरी, अशवनी शर्मा, अध्यक्ष-समीर सिंह, मिडिया प्रभारी- विजय शंकर नायक, कार्यकारी अध्यक्ष- ममता देवी, उमेश कुमार राय, शिव कुमार वर्मा, उपाध्यक्ष- विनय कुमार दुबे(पहलवान), पंकी सिंह, रुक्मणी देवी, अमर कुमार शास्त्री, कामता यादव सचिव- कुमार सावन, सहसचिव- संजय सिन्हा, अजय कुमार, श्याम किशोर सिंह, श्याम पाण्डेय, प्रमोद ठाकुर, लव कुश यादव, विजेन्द्र शर्मा, कोषाध्यक्ष- सत्यम कुमार दत्ता, सह- कोषाध्यक्ष- चन्द्र देव ठाकुर, लेखापाल- अमर वर्मा, शिवानी सिंह सह- लेखापाल - हर्षित कुमार , सुगम कुमार , सदस्यता- बिंदू प्रसाद बनाये गये है । धन्यवाद ज्ञापन इस कार्यक्रम के संयोजक ब्रजेश कुमार ने किया। उपरोक्त जानकारी श्री राम कथा आयोजन कार्यक्रम के मीडिया प्रभारी विजय शंकर नायक ने साझा किया।

फार्मर रजिस्ट्री में 81.92% के साथ जिला प्रदेश में दूसरे स्थान पर, इतने किसानों ने कराया पंजीयन

सिरोही। केन्द्र सरकार की एग्रीस्टेक योजना के तहत फार्मर रजिस्ट्री शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। जिले में 65,965 किसान किसान लाभार्थियों के विरुद्ध 54,069 किसानों का पंजीकरण अब तक किया जा चुका है। फार्मर रजिस्ट्री में प्रदेश में सिरोही जिला दूसरे स्थान पर रहा है। जिले में 65,965 पीएम किसान लाभार्थियों के विरुद्ध 54,069 किसानों का

पंजीकरण किया जा चुका है, जो लक्ष्य का 81.92 प्रतिशत है। 24 मार्च 2025 को जारी की गई समीक्षा रिपोर्ट के आधार पर सिरोही जिला राज्य स्तरीय रैंकिंग में दूसरे पायदान पर रहा है। जिला कलेक्टर ने उपखंड अधिकारियों को शत-प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त करने के आदेश दिए हैं। जिला कलेक्टर उत्पला चौधरी ने बताया कि उपखंड अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वर्तमान में फार्मर रजिस्ट्री

शिविरों का कार्यक्रम अपने अंतिम चरण में है। इस महीने के अंतिम सप्ताह में शत-प्रतिशत काशतकारों का पंजीकरण सुनिश्चित करने के लिए डोर-टू-डोर संपर्क करना आवश्यक है। इसके लिए ई-केवाईसी हेतु ग्राम विकास अधिकारी, पंचायत कनिष्ठ सहायक तथा भूमि सत्यापन के लिए पट्टवारियों की पंचायतवार संचालित की पंचायतवार संचालित की गयी है कि निर्देश दिए गए

इंद्रप्रस्थ इंजीनियरिंग कॉलेज में दो दिवसीय अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में जुटे शिक्षाविद



नेशनल प्रेस टाइम ब्यूरो

साहिबाबाद। इंद्रप्रस्थ इंजीनियरिंग कॉलेज में बहुविषयक अनुसंधान में उभरते रुझानर विषय पर दो दिवसीय अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का भव्य आयोजन किया गया। इस सम्मेलन का उद्घाटन मुख्य अतिथि प्रो. डॉ. एन.एच. सुब्बलिंगा स्वामी (सलाहकार, छात्रवृत्ति एवं अनुदान ब्यूरो, एआईसीटीई), पुनीत अग्रवाल (वाइस चेरमैन), डॉ. अजय कुमार (निदेशक), डॉ. संजय सिंह (कैंपस निदेशक, एमआईईटी मेरठ), डॉ.

मीनाक्षी शर्मा (डीन, छात्र कल्याण), डॉ. जुगल किशोर गुप्ता सहित अन्य गणमान्य अतिथियों ने दीप प्रज्वलित कर किया।

सम्मेलन के मुख्य वक्ता प्रो. डॉ. अक्षय द्विवेदी (डीन, एसआरआईसी, आईआईटी रुड़की) और डॉ. मुत्थु सिंगाराम (आईआईटी मद्रास) ने अनुसंधान और प्रौद्योगिकी में नवीनतम रुझानों पर अपने विचार साझा किए।

सम्मेलन में 90 से अधिक शोधपत्र प्राप्त हुए, जिनमें से 60 शोधपत्रों को संशोधन के उपरांत



स्वीकृति प्रदान की गई। सभी शोधपत्रों की मौलिकता की जांच सॉफ्टवेयर के माध्यम से की गई। इस सम्मेलन को रूस, शिकागो, कनाडा सहित दिल्ली प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, जामिया मिलिया इस्लामिया, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, नेताजी सुभाष प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय और अन्य प्रतिष्ठित भारतीय एवं विदेशी संस्थानों से शोधपत्र प्राप्त हुए, जो इस आयोजन की वैश्विक प्रासंगिकता को दर्शाता है। तकनीकी सत्रों के दौरान नवीन विषय रमेशोरी उपकरणों में नैनोइलेक्ट्रॉनिक्स पर प्रो. (डॉ.)

सज्जाद अहमद लोन (जामिया मिलिया इस्लामिया) ने अपने विचार प्रस्तुत किए। इस महत्वपूर्ण अवसर पर डॉ. जुगल किशोर गुप्ता, डॉ. मीनाक्षी शर्मा, डॉ. विजई सिंह, डॉ. राणा तबस्सुम, डॉ. पूजा द्विवेदी, डॉ. स्वाति वेद एवं अरुण कुमार शुक्ला का विशेष योगदान रहा।

अंतरराष्ट्रीय स्तर के इस सम्मेलन ने बहुविषयक अनुसंधान और नवाचार को नई दिशा देने का कार्य किया, जिसमें शिक्षाविदों और शोधकर्ताओं ने अपने विचारों का आदान-प्रदान किया।

एलआईयू को सूचना एकत्रित करने के लिए दायरा बढ़ाने के निर्देश

नेशनल प्रेस टाइम ब्यूरो

बुलंदशहर। डीआईजी कलानिधि नैथानी ने बुधवार को पुलिस कार्यालय, नगर कोतवाली, रिक्रूट आरक्षी प्रशिक्षण केंद्र का वार्षिक निरीक्षण किया। साथ ही अभियोजन में बुलंदशहर रेंज में प्रथम स्थान पर रहने पर प्रशंसा की। आगामी त्योहार अलविदा जुमा, ईद व नवरात्र, रामनवमी के दृष्टिगत शहर स्थित शाही ईदगाह व राजराजेश्वर मंदिर का भ्रमण किया गया। उन्होंने नगर कोतवाली का आकस्मिक निरीक्षण किया। उन्होंने एलआईयू को सूचना एकत्रित करने के लिए अपना दायरा बढ़ाने के निर्देश दिए। पुलिस कार्यालय का भ्रमण कर उच्चैकृत करने और कार्यालय को आगंतुक सुलभ बनाने, बीट कर्मी के कार्यों की समीक्षा करने के साथ सभी एलआईयू कर्मियों को निर्देश दिए कि अपनी बीट में रहें। मुख्यालय से बीट न चलाएं। शहर एलआईयू की बीट में कम से कम एक दारोगा नियुक्त करें, जो सीधे एसपी सिटी/एसपी को रिपोर्ट करें। कर्मियों का बीट निर्धारण सही करें और एसएसपी



कार्य वितरण की समीक्षा करें। बीट प्रभावी देखें की नए नए दल कलक्टेक्ट में ज्ञापन देते हैं। उनके कार्ड जारी करें तथा जो लोग आदतन धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उनके कार्ड खोले जाएं।

विदेशी नागरिकों के आवागमन पर विशेष ध्यान दें। इसके लिए होटल आदि समय से सूचना दें, विलंब करने या सूचना छिपाने पर होटल को नोटिस जारी करें एवं विदेशी अधिनियम में मुकदमा दर्ज करें। जमात में जिले में आने वाले व जमात के लिए बाहर जाने वाले लोगों के बारे में सूचना संकलन कर वरिष्ठ अधिकारियों को समय से अवगत कराएं। अलविदा जुमा, ईद, नवरात्र रामनवमी आदि पर कुशल कर्मियों की ड्यूटी लगाएं।

नए कानून बीएनएस के तहत महिला संबंधी अपराध में जिले में सजा

काई गई है। आपरेशन कन्विकशन अभियान के तहत अभियोग चिह्नित कर प्रभावी पैरवी कर अधिक से अधिक सजा कराएं। सबसे पुराने 50 केसों की सूची अभियोजन शाखा, पुलिस विभाग को उपलब्ध करा दें ताकि पैरवी करके उनका शीघ्र निस्तारण कराया जा सके।

कोर्ट पैरोकार, सम्मन वारंटों की प्रतिदिन थाने में एंट्री कराएं। इस दौरान एसएसपी शोका कुमार, संयुक्त निदेशक अभियोजन नवीन कुमार दूबे, डीजीसी क्रिमिनल राहुल उपाध्याय, एसपी सिटी शंकर प्रसाद, एसपी अपराध नरेश कुमार, एसपी लाइन ऋजुल, प्रभावी एलआईयू निरीक्षक नरेश कुमार उपस्थित रहे।

गाजियाबाद की हवा खराब!ः ये इलाका बना गैस चैंबर, मार्च में ही AQI पहुंच गया 424; बना देश का तीसरा प्रदूषित शहर



गाजियाबाद। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में हवा की गुणवत्ता खराब है। लोनी इलाके में वायु गुणवत्ता सूचकांक 424 दर्ज हुआ है। जो गंभीर श्रेणी में है। मार्च के महीने में ही गाजियाबाद में हवा खराब हो रही है। गाजियाबाद में अधिकारियों की लापरवाही और अनदेखी लोगों की सेहत पर भारी पड़ रही है। बुधवार को लोनी गैस चैंबर बन गया। यहां शाम पांच बजे सीपीसीबी के समीर एफ पर यहां का वायु गुणवत्ता सूचकांक 424 दर्ज किया गया। इसके साथ ही गाजियाबाद और इंदिरापुरम का एक्वआई भी 300 के पार पहुंच गया। बड़े हुए एक्वआई के साथ गाजियाबाद देश का तीसरा सबसे प्रदूषित शहर रहा। शहर की हवा हर दिन बिगड़ती जा रही है।

बावजूद इसके न तो लोगों की लापरवाही कम हुई है और न ही अब तक विभागीय अधिकारियों ने कोई निगरानी ही शुरू की है। लोनी में हर दिन कूड़े के ढेर में आग लगाई जा रही है। दो दिन पूर्व भी कूड़े के ढेर में आग लगी थी। वहीं बुधवार को भी टीला मोड़ क्षेत्र में सड़क किनारे कूड़े के ढेर में आग लगाई गई।

गाजियाबाद में वारदात: प्रधानाचार्य से लूटा मोबाइल और रुपये, फिर चलते ऑटो से दिया धक्का

नेशनल प्रेस टाइम ब्यूरो

गाजियाबाद। गाजियाबाद में दिल्ली के छज्जपुर में रहने वाले इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य से लूटपाट की वारदात सामने आई है। ऑटो चालक ने अपने साथियों के साथ मिलकर वारदात को अंजाम दिया है।

शहर में ऑटो चालक सवारियों से लूटपाट की वारदातों को लगातार अंजाम दे रहे हैं। सहारनपुर स्थित इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य से भी ऑटो चालक और उसके साथी ने लूटपाट की। विरोध करने पर चलते ऑटो से सड़क पर धक्का दे दिया। इससे प्रधानाचार्य घायल हो गए। घायल ने नंदग्राम थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। साथ ही ऑटो की सीसीटीवी फुटेज भी पुलिस को सौंपी है।

दिल्ली के छज्जपुर क्षेत्र की गली नंबर चार निवासी चंद्र किशोर



(48) ने बताया कि वह सहारनपुर स्थित स्टार पेपर मिल के नजदीक सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कालेज में प्रधानाचार्य के पद पर तैनात हैं। बताया कि शनिवार को वह चंदौसी निवासी अपने बेटी के घर गए थे। रात करीब नौ बजे वह लाल कुआं उतरे और ऑटो में सवार होकर रेलवे रोड पर उतर गए। जहां से नीले रंग के बैटरी चालित ऑटो में

मोहननगर जाने के लिए सवार हो गए।

प्रधानाचार्य ने बताया कि ऑटो में चालक के साथ एक अना युवक भी पीछे बैठा था। दोनों ने मोहन नगर जाने के लिए दूसरा रास्ता बताया और राजनगर एक्सप्रेसन रोड की ओर ऑटो दौड़ा दिया। विरोध करने पर उन्होंने सुनमान जंगल पर ऑटो रोका और चाकू दिखाकर जेब में

रखा पर्स और पांच हजार रुपये की नकदी के साथ-साथ मोबाइल भी लूट लिया। ऑटो चालक ने धमकी दी कि शोर मचाने पर हत्या कर दी जाएगी।

प्रधानाचार्य ने बताया कि उन्होंने ऑटो चालक से निम्नत की कि सुनसान स्थान को वह नहीं जानते उन्हें सड़क तक छोड़ दें यह घटना की बात किसी को नहीं बताएंगे। दोनों ने प्रधानाचार्य को ऑटो में बैठाया और सड़क पर लाकर चलते ऑटो से धक्का दे दिया। जिसके बाद पीड़ित पैदल एक मंदिर पर पहुंचे और पुलिस कंट्रोल रूम को सूचना दी।

पुलिस ने घायल का प्राथमिक उपचार कराया। जहां से पीड़ित चंद्र किशोर नंदग्राम थाने में तहरीर देकर दिल्ली लौट गए। पुलिस ने बीएनएस के तहत झपटमारी करने की धारा 304 में मुकदमा दर्ज कर लिया है।

टीबी मुक्त गाजियाबाद और टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत टीबी के बारे में विस्तार से दी जानकारी

नेशनल प्रेस टाइम ब्यूरो

गाजियाबाद। सेहत सही लाभ कई स्मार्ट के सौजन्य से टीबी मुक्त भारत अभियान को लेकर सामुदायिक रेडियो स्टेशन जागरूकता कार्यक्रम चला रहे हैं। इसी कड़ी में हिन्ट रेडियो ने आरडीसी स्थित चाय की टपरियों पर बैठकर चुस्की व धुआं उड़ाने वाले युवा वर्ग के बीच पहुंचकर नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत कर उन्हें टीबी रोग के बारे में विस्तार से जानकारी दी। युवाओं को बताया गया कि टीबी की बीमारी कोई



गरीबों की बीमारी नहीं है बल्कि यह तो लापरवाही बरतने पर किसी को भी हो सकती है। अतः टीबी मुक्त गाजियाबाद और टीबी मुक्त भारत अभियान चलाया जा

रहा है। हिन्ट रेडियो की टीम ने नुक्कड़ नाटक की प्रस्तुति देने वाली युवाओं की टीम को इतने बेहतर ढंग से अपनी बात युवाओं तक पहुंचाने पर अपना आभार व्यक्त किया।

खरीदारों को बड़ा झटका: ग्रेटर नोएडा में महंगी होगी रजिस्ट्री, सर्किल रेट में 70 प्रतिशत की वृद्धि

नेशनल प्रेस टाइम ब्यूरो

ग्रेटर नोएडा। गौतमबुद्ध नगर जिला प्रशासन ने सर्किल रेट में 15 से 70 प्रतिशत की वृद्धि की है। जिसको लेकर सर्किल रेट की प्रस्तावित दरों की सूची जारी की गई है। लोग प्रस्तावित दरों पर 5 अप्रैल तक आपत्ति दर्ज करा सकते हैं।

जिला प्रशासन ने सर्किल रेट की प्रस्तावित दरों का बदलाव के साथ प्रकाशन कर दिया है। अलग-अलग श्रेणी की भूमि में 15 से 70 प्रतिशत तक की वृद्धि की गई है। जेवर तहसील में कृषि भूमि के सर्किल रेट में 70 प्रतिशत तक की वृद्धि की गई है। जबकि नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना प्राधिकरण में फ्लैटों की रजिस्ट्री भी महंगी हो जाएगी। यहां सर्किल रेट में 20 से 30 प्रतिशत तक की वृद्धि प्रस्तावित की है। प्रशासन ने प्रस्तावित दरों पर जिले के लोगों से 5 अप्रैल तक आपत्तियां मांगी है। आपत्तियों को निस्तारण करने के बाद प्रशासन सर्किल रेट की नई दरों को लागू करेगा।

गौतमबुद्ध नगर में वर्ष 2016 के बाद से सर्किल रेट की दरों में बदलाव नहीं हुआ है। अब किसानों के दबाव और सरकार के आदेश पर जिला प्रशासन ने सर्किल रेट की दरों में बदलाव किया है। जेवर तहसील में कृषि भूमि के सर्किल रेट में 70 प्रतिशत की वृद्धि की है। अभी जेवर में कृषि भूमि का सर्किल रेट में



900 रुपये प्रति वर्ग मीटर है। इसको बढ़ाकर 1550 रुपये प्रति वर्ग मीटर किया गया है। हाल ही में सरकार ने एयरपोर्ट से प्रभावित किसानों की जमीन का मुआवजा 4300 रुपये प्रति वर्ग मीटर किया है। अब प्रस्तावित सर्किल रेट भी उसी हिसाब से तय किया गया है। पिछली बार वर्ष 2016 में जेवर क्षेत्र में कृषि भूमि के सर्किल रेट में 15 से 20 प्रतिशत की वृद्धि की गई थी।

प्राधिकरण के भूखंडों में 10 से 20 प्रतिशत वृद्धि प्रशासन ने नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना प्राधिकरण के आवासीय, ग्रुप हाउसिंग, औद्योगिक, आईटी, आईटीईएस, वाणिज्यिक भूखंड व वाणिज्यिक संपत्तियों के सर्किल रेट में भी वृद्धि की है। तीनों जगह सर्किल रेट 10 प्रतिशत बढ़ाया गया है। हालांकि जेवर तहसील के वाणिज्यिक भूखंड और वाणिज्यिक संपत्तियों के सर्किल रेट में 18 से 20 प्रतिशत की वृद्धि

प्रस्तावित की है। उधर कार्यालय उपयोग के भूखंडों के सर्किल रेट में 15 प्रतिशत की वृद्धि की है।

नोएडा से महंगी होगी ग्रेने में फ्लैटों की रजिस्ट्री

नोएडा और ग्रेटर नोएडा के दो लाख से अधिक खरीदारों पर रजिस्ट्री का अतिरिक्त बोझ पड़ने वाला है। प्रशासन ने फ्लैटों की रजिस्ट्री के सर्किल रेट में 20 से 30 प्रतिशत तक की वृद्धि की गई है। नोएडा में मल्टीस्टोरी बिल्डिंग के फ्लैट व अपार्टमेंट की दरों में 20 प्रतिशत का इजाफा किया गया है। जबकि दादरी और सदर तहसील क्षेत्र में 30 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। ऐसे में जो खरीदार लंबे समय से रजिस्ट्री होने का इंतजार कर रहे हैं, उन पर अतिरिक्त भार पड़ेगा। साथ ही नए खरीदारों पर भी रजिस्ट्री का अतिरिक्त भार पड़ेगा।

‘नेशनल प्रेस टाइम्स’

दैनिक समाचार पत्र में एनसीआर के जनपदों के लिए ब्यूरो चीफ, तहसील ब्यूरो, संपादकता व मार्केटिंग के लिए इच्छुक लड़के व लड़की सम्पर्क करें।

विज्ञापन, न्यूज, आदि के लिए सम्पर्क करें।

सुखपाल सिंह (संपादक)

प्रमोद मिश्रा (सह-संपादक)

8448184482

एस.के. राणा (सह-संपादक)

8938805409

पता : 209, द्वितीय तल, दुर्गा चैम्बर, आरडीसी, राजनगर, गाजियाबाद

फोन- 0120-4549844, मो. 9312606107

nationalpresstimes@gmail.com/

www.nationalpresstimes.com

नेशनल प्रेस टाइम्स की तरफ से गुप्त कानूनी सलाह के लिए सम्पर्क कर सकते हैं।

एडवोकेट आदर्श कुमार राय

(इलाहाबाद हाईकोर्ट)

09415624173